कृषि | विश्लेषण | जल प्रबंधन

कुल पृष्ठः 40

स्वदेशी पत्रिका

मूल्य 15/–रू.

वैशाख–ज्येष्ठ 2083, मई 2026

स्वदेशी गतिविधियां

स्वदेशी कार्यक्रम

सचित्र झलक

भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, खानपुर कलां

भुवनेश्वर, उड़ीसा

भूमि सुपोषण कार्यक्रम, आंध्र प्रदेश

हैदराबाद, आंध्र प्रदेश

स्वदेशी पत्रिका

अ नु क्र म

वर्ष–34, अंक–5
वैशाख–ज्येष्ठ 2083 मई 2026

संपादक
अजेय भारती

सह–संपादक
अनिल तिवारी

पृष्ठ सज्जा एवं टंकन
सुदामा दीक्षित

कार्यालय
धर्मक्षेत्र, सेक्टर–8, बाबू गेनू मार्ग
रामकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली–110022
से प्रकाशित

दूरभाष : 011–26184595

स्वदेशी जागरण समिति की ओर से डॉ. अश्वनी महाजन द्वारा कॉम्पीटेंट बाइन्डर्स (प्रिंटिंग यूनिट), नवीन शाहदरा, दिल्ली–32 से मुद्रित।

पाठकनामा / उन्होंने कहा **4**
समाचार परिक्रमा **36-38**

तृतीय मुख्य पृष्ठ **39**
चतुर्थ मुख्य पृष्ठ **40**

आवरण कथा – पृष्ठ–06

रुपये को मजबूती के लिए जरूरी है आत्मनिर्भरता
डॉ. अश्वनी महाजन

1 मुख्य पृष्ठ
2 द्वितीय मुख्य पृष्ठ

09 आजकल
ईरान–अमेरिका युद्ध और भारत की ऊर्जा–आर्थिक सुरक्षा ..... *डॉ. धनपत राम अग्रवाल*

13 ऊर्जा संकट
वर्तमान ऊर्जा संकट के दौर में आर्थिक संयम की जरुरत ..... *दुलीचंद कालीरमन*

15 आत्मनिर्भर भारत
महंगे दिन से निपटने का मंत्र है आत्मनिर्भरता ..... *अनूप पांडे*

17 अंतर्राष्ट्रीय
वैश्विक चुनौतियों के मद्देनजर भारत को चाहिए नई तरकीब ..... *अनिल तिवारी*

19 धरोहर
अटूट आस्था का शाश्वत प्रतीक सोमनाथ ..... *योगी आदित्यनाथ*

21 बहस
देश वापसी की अपील के मायने ..... *स्वदेशी संवाद*

23 शिक्षा
ज्ञान के मंदिर पर बाजार का कब्ज़ा ..... *विजय गर्ग*

25 विश्लेषण
खतरनाक है गर्मी की आपदा ..... *डॉ. दिनेश प्रसाद मिश्र*

27 चिकित्सा
'आयुष्मान–भारत' से कम हो रहा है इलाज का बोझ ..... *गणेश गौतम*

30 मुद्दा
परीक्षाओं पर दिलाना होगा छात्रों का भरोसा ..... *शिवनंदन लाल*

32 अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस
श्रमेव जयते! का यशोगान ..... *हेमेन्द्र क्षीरसागर*

34 रिपोर्ट
आईआईटी रुड़की में "विजन 2047–समृद्ध एवं महान भारत 2.0" पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन ..... *स्वदेशी संवाद*

पाठकनामा

'वैश्विक ऊर्जा संकट और भारत का आर्थिक कवच'

वर्तमान समय में भारत एक अभूतपूर्व वैश्विक ऊर्जा संकट और घरेलू मोर्चे पर हॉस्टलों के प्रबंधन जैसी प्रशासनिक चुनौतियों से एक साथ निपट रहा है। पश्चिम एशिया में बढ़ते भू–राजनीतिक तनाव और 'स्ट्रेट ऑफ हार्मुज' के बाधित होने से कच्चे तेल और रसोई गैस (एलपीजी) की आपूर्ति पर भारी दबाव बना है। भारत अपनी जरूरत का 85 प्रतिशत तेल आयात करता है, जिससे देश का आयात बिल तेजी से बढ़ा है और एलपीजी सिलेंडरों की राशनिंग (शहरी क्षेत्रों में 25 दिन की सीमा) करनी पड़ी है। इस संकट के स्थाई समाधान के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में यूएई, नॉर्वे और यूरोपीय देशों का कूटनीतिक दौरा (टूर डिप्लोमेसी) किया। यूएई के साथ दीर्घकालिक एलपीजी समझौते और रणनीतिक तेल भंडारण के फैसलों ने भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत किया है, जबकि नॉर्वे जैसे देशों से गैर–खाड़ी तेल के विकल्प तलाशे जा रहे हैं। साथ ही, सरकार दीर्घकालिक समाधान के रूप में 'मल्टी–फ्यूल स्ट्रेटजी' के तहत ई–कुकिंग (इंडक्शन), बायोगैस और ग्रीन हाइड्रोजन को तेजी से बढ़ावा दे रही है।

इस तेल संकट के कारण भारत के डॉलर भंडार (फॉरेक्स रिजर्व) पर दबाव पड़ा है, जिससे यह 700 बिलियन डालर से थोड़ा घटकर 691 बिलियन डालर के स्तर पर आ गया है। यही कारण है कि प्रधानमंत्री और सरकार ने सभी देशवासियों से संसाधनों (तेल, गैस और सोने) का 'संभालकर और समझदारी से इस्तेमाल करने की अपील की है। सरकार की इस सलाह का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि देश में इन चीजों की कोई कमी है।' भारत के पास पर्याप्त स्टॉक और सुरक्षा भंडार मौजूद है, लेकिन इस किफायत का उद्देश्य देश के मूल्यवान विदेशी मुद्रा भंडार (डॉलर) को बचाना और अंतरराष्ट्रीय बाजार में अनावश्यक खर्च को रोकना है ताकि अर्थव्यवस्था को महंगाई से सुरक्षित रखा जा सके।

इसके साथ ही, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विदेशों (बैंक ऑफ इंग्लैंड) से अपने सोने के खजाने की ऐतिहासिक 'घर वापसी' (लगभग 880 टन का सुरक्षा कवच) कराने और अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने के दाम बढ़ने से भारत की अर्थव्यवस्था बेहद सुरक्षित और आत्मनिर्भर स्थिति में है। कुल मिलाकर, भारत अपनी मजबूत कूटनीति, जनता के आंतरिक अनुशासन और विशाल स्वर्ण भंडार के दम पर इस वैश्विक आर्थिक चक्रव्यूह को सफलतापूर्वक भेद रहा है।

विजित कुमार, क्षेत्र मीडिया प्रमुख, पूर्वोत्तर भारत, स्वदेशी जागरण मंच

आवश्यक नहीं कि इस अंक के भीतर प्रस्तुत लेखकों के विचार स्वदेशी पत्रिका के संपादक मंडल के विचारों से मेल खाते हों। पाठकों की जानकारी के लिए उन्हें यहां प्रस्तुत किया जा रहा है।

संपादकीय कार्यालय

''धर्मक्षेत्र'' शिव शक्ति मन्दिर, सैक्टर–8, रामकृष्णपुरम्,
नयी दिल्ली–110022

दूरभाष : 011–26184595 • ई–मेलः
swadeshipatrika@rediffmail.com

अगर आप घर बैठे स्वदेशी पत्रिका चाहते हैं तो डिमांड ड्राफ्ट, मनीऑर्डर अथवा चेक द्वारा शुल्क *'स्वदेशी पत्रिका'* दिल्ली के नाम भेजने का कष्ट करें।

वार्षिक सदस्यता शुल्क : 150 रुपए
आजीवन सदस्यता शुल्क: 15,00 रुपए

यदि शुल्क जमा करने के उपरांत भी आपको पत्रिका समय पर उपलब्ध नहीं हो पा रही है तो तुरंत पत्रिका कार्यालय को सूचित करें।

या आप सीधे बैंक ऑफ इंडिया, खाता नं. 602510110002740
IFSC : BKID 0006025 (Ramakrishnapuram)

कहा–अनकहा

संस्कृत भारत की जीवन शक्ति है जिसके माध्यम से विचारों, जीवन और संस्कृति की सबसे प्राचीन जीवंत परंपरा आज भी विद्यमान है।

डॉ. मोहन भागवत, सरसंघचालक, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ

दुनिया के पहले आटोएसएआर उपग्रह और भारत में निजी तौर पर निर्मित सबसे बड़े उपग्रह का सफल प्रक्षेपण, नवाचार और राष्ट्र–निर्माण के प्रति हमारे युवाओं के जुनून का एक प्रमाण है।

नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री, भारत

हम जो देख रहे हैं, वह अलग–थलग घटनाओं की एक शृंखला नहीं है, बल्कि चुनौतियों का एक ऐसा संगम है जो बहुपक्षीय व्यवस्था के लचीलेपन की परीक्षा ले रहा है।

एस. जयशंकर, विदेश मंत्री, भारत

स्वदेशी जागरण मंच का दृढ़ विश्वास है कि प्रधानमंत्री की यह ओजस्वी पुकार देश की मानसिकता पर निश्चित रूप से गहरा प्रभाव डालेगी, जो न केवल लोगों को पेट्रोलियम उत्पादों की खपत कम करने के लिए प्रोत्साहित करेगी, बल्कि हमारे वैज्ञानिकों, शिक्षाविदों और उद्योगों को भी हमारी दैनिक आवश्यकताओं के लिए पेट्रोलियम उत्पादों के नए विकल्प खोजने हेतु प्रेरित करेगी।

डॉ. अश्वनी महाजन, राष्ट्रीय सहसंयोजक, स्वदेशी जागरण मंच

संपादकीय

घुसपैठ का निदान है जरूरी

हाल ही में भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा स्पेशल इंटेंसिव रिलिजन (एसआईआर) की एक प्रक्रिया शुरू की गई, जिसके अंतर्गत अभी तक कई राज्यों में चुनाव से पूर्व इस प्रक्रिया के माध्यम से किसी विदेशी के मतदाता सूची में गलती से शामिल होने, मृत वोटरों के मतदाता सूची से नाम न हटने, किसी वोटर के एक स्थान से ज्यादा स्थानों पर मतदाता सूची में शामिल होने और बार–बार पलायन के कारण मतदाता सूची की कमियों को दुरूस्त करने का काम किया जा रहा है। स्वभाविकतौर पर विदेशियों के नाम मतदाता सूची में होने की स्थिति में, एसआईआर प्रक्रिया के कारण उनके नाम स्वयमेव कट जाते हैं, क्योंकि वे अपनी नागरिकता सिद्ध नहीं कर पाते। हालांकि विपक्षी दलों द्वारा एसआईआर प्रक्रिया की पुरजोर खिलाफत हुई, लेकिन अंतोत्गत्वा सर्वोच्च न्यायालय ने एसआईआर प्रक्रिया को संवैधानिक ठहराते हुए विपक्ष की आपत्तियों को खारिज कर दिया है। एसआईआर के माध्यम से हालांकि बड़ी संख्या में विदेशी घुसपैठियों के नाम मतदाता सूची से हटाने का काम तो हुआ है, लेकिन विदेशी घुसपैठियों को देश से बाहर करने का महत्वपूर्ण कार्य अभी बाकी है। पिछले लम्बे समय से भारत के विभिन्न भागों में अवैध बंगलादेशी घुसपैठ का खतरा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। दुनिया में कहीं भी अवैध विदेशी घुसपैठ को अनुमति नहीं है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारत में इस मुद्दे को राजनीतिक रंग देने का प्रयास किया जाता रहा है।

हाल ही में भारत के गृहमंत्री अमित शाह ने अवैध घुसपैठ के मामले और जनसांख्यिकी बदलाव (डेमोग्राफिक चेंज) पर उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। इसके पीछे की पृष्ठभूमि यह मानी जा रही है कि बंगलादेश के साथ सांझी सीमा होने और पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री सुश्री ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा राज्य में बंगलादेशी घुसपैठियों को प्रश्रय देने के कारण पश्चिम बंगाल में बंगलादेशी घुसपैठ की समस्या ने विकराल रूप धारण किया हुआ है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का शासन स्थापित होने के तुरंत बाद इस समिति के गठन के बाद यह स्पष्ट है कि अवैध बंगलादेशी घुसपैठ के खिलाफ अब सरकार सख्त रूख अपनाने वाली है। विपक्षी दल, जब वे सत्ता में थे, तब भी वे इस समस्या का जिक्र तो करते थे, लेकिन समाधान के नाम पर उन्होंने कोई प्रकट प्रयास नहीं किया। वर्तमान सरकार के प्रयासों से वे कभी सहमत नहीं हुए, और आज भी इस मुद्दे के बारे में सरकार के साथ एक राय नहीं रखते। इस मुद्दे को राजनीति के चश्में से न देखकर, देश और समाज के हित के साथ जोड़कर देखने की जरूरत है। समझना होगा कि विदेशी घुसपैठ के मुद्दे के कई पहलू हैं। यह विषय मात्र जनसंख्या परिवर्तन का ही नहीं है। इसके कई दूरगामी आयाम है, जिन्हें समझने की जरूरत है। बांग्लादेशिओं अवैध घुसपैठ के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और कानून–व्यवस्था से जुड़े प्रभावों से देश आज जूझ रहा है। हालांकि इसके प्रभाव पूरे देश में एक जैसे नहीं हैं; सीमावर्ती और सघन शहरी इलाक़ों जैसे असम, पश्चिम बंगाल और दिल्ली व मुंबई अवैध घुसपैठ की परिणाम ज़्यादा स्पष्ट दिखाई दे रहा है। यदि घुसपैठ के आर्थिक परिणामों की बात करें, तो सबसे पहले तो घुसपैठ भारत के नागरिकों के रोजगार पर प्रहार करती है। भारत पहले से ही एक विशाल जनसंख्या और युवा आबादी वाला देश है। देश के लोगों, खासतौर पर युवाओं को रोजगार मिलने में कठिनाई हो रही है, लेकिन ऐसे में जब बंगलादेशी घुसपैठिए रोजगार पाने की कवायद में सस्ती से सस्ती मजदूरी पर काम करने के लिए तैयार रहते हैं, ऐसे में भारतीय मजदूर रोजगार से बाहर हो जाते हैं। घरेलू काम हो अथवा औद्योगिक रोजगार सभी में बंगलादेशी घुसपैठिए भारत के नागरिकों को रोजगार से बाहर कर रहे हैं। यही नहीं भारत में रोजगार में असंगठित क्षेत्र जिसमें छोटे दुकानदार, रेहड़ी पटरी, खोमचा, कबाड़, निर्माण और बाजारों और मंडियों में भारी मात्रा में रोजगार सृजन होता है। इन सभी स्थानों पर बंगलादेशी घुसपैठिए रोजगार पर कब्जा कर रहे हैं और कई बार तो पूरा सिंडिकेट बनाकर वे काम करते हैं। छोटे दुकानदार और व्यापारियों को इससे भारी नुकसान हो रहा है। यही नहीं चूंकि बंगलादेशी घुसपैठिए असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, जिससे सरकार को कोई राजस्व नहीं मिलता। इसके साथ ही वे भारत से पैसा कमाकर वे अवैध तरीके से बंगलादेश में भी पैसा भेजते हैं, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था को नुकसान होता है। इसके अलावा भारत सरकार देश के गरीब नागरिकों के लिए जो कल्याणकारी योजनायें चलाती है, जिसके तहत मुत रशन, बिजली, पानी और वित्तीय समावेशन (जैसे बैंक खाते) जैसी सुविधाएं दी जाती है, फर्जी दस्तावेजों के दम पर ये घुसपैठिए इन योजनाओं का अनुचित लाभ उठा रहे हैं, जिससे देश के खजाने को हर साल करोड़ों का नुकसान हो रहा है।

नकली आधार, राशन कार्ड और वोटरकार्ड के मामले शासन–प्रशासन और आंतरिक सुरक्षा के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। इससे नागरिकों और गैर–नागरिकों के बीच अंतर कर पाना और भी कठिन हो जाता है। घुसपैठ के कारण हो रहे जनसांख्यिकीय बदलावों के चलते सांस्तिक या भाषाई असंतुलन उत्पन्न होता है, सीमावर्ती जिलों में यह ज़्यादा दिखाई देता है।संसाधनों (भूमि, रोजगार, कल्याणकारी योजनाएं) के लिए प्रतिस्पर्धा से स्थानीय आबादी और प्रवासी समुदायों के बीच टकराव उत्पन्न होता है। घुसपैठ वाले इलाक़ों में दंगों की आशंकाएँ भी भी ज़्यादा होती हैं। मानव तस्करी, संगठित अपराध, सार्वजनिक भूमि पर अवैध क़ब्ज़े जैसे अपराध भी अक्सर घुसपैठ के साथ जुड़े हुए होते हैं। इस बात के आरोप भी अक्सर लगते रहे हैं कि कुछ राजनीतिक दल चुनावी लाभ के लिए अवैध घुसपैठ को बढ़ावा देते हैं या उसकी अनदेखी कर रहे हैं। इससे राजनीतिक विमर्श में ध्रुवीकरण बढ़ता है और प्रशासन के सामने चुनौतियाँ खड़ी होती हैं। कुछ राजनीतिक दलों द्वारा अल्पसंख्यकों का अनावश्यक तुष्टीकरण भी देखने को मिलता है, जो कुछ धार्मिक समूहों की श्वोट बैंकश की राजनीति में विश्वास रखते हैं। इस प्रकार स्वच्छ राजनीतिक मूल्यों का क्षरण होता है। अनेक बार चुनाव के नतीजे भी अवैध घुसपैठियों द्वारा प्रभावित होने लगते हैं, जिससे स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था पर आघात पहुंचता है। समझा जा सकता है घुसपैठ की समस्या के निदान हेतु वर्तमान सरकार द्वार किए जाए रहे प्रयास यदि फलीभूत हों तो इससे आर्थिक सामाजिक राजनीतिक ताने बाने पर आ रहे संकट का भी काफ़ी निदान हो पाएगा।

रुपये को मजबूती के लिए जरूरी है आत्मनिर्भरता

हालांकि, भारतीय रुपया लंबे समय से कमज़ोर हो रहा है, लेकिन अमेरिका, इज़रायल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध के ढ़ाई महीने की बहुत छोटी सी अवधि में रुपये के मूल्य में आई हालिया गिरावट नीति निर्माताओं के लिए चिंता का एक बड़ा कारण है। हालांकि, भारतीय रुपये के मूल्य में गिरावट का सीधे तौर पर ज़िक्र नहीं किया गया, लेकिन यह कोई भी समझ सकता है कि जब 10 मई, 2026 को प्रधानमंत्री ने राष्ट्र से पेट्रोल और डीज़ल बचाने की अपील की – जिसके लिए उन्होंने अनावश्यक पेट्रोल–डीज़ल से चलने वाले वाहनों का इस्तेमाल कम करने, विदेश यात्रा में कटौती करने, घर से काम करने और ऑनलाइन बैठकें करने का सुझाव दिया – तो असल में यह नागरिकों से विदेशी मुद्रा बचाकर भारतीय रुपये की रक्षा करने की अपील ही थी। इसी संदर्भ में, प्रधानमंत्री की नागरिकों से सोने की खरीद से बचने, खाना पकाने के तेल की खपत कम करने, विदेशी ब्रांड के सामान न खरीदने और स्वदेशी उत्पादों का उपयोग करने, रासायनिक उर्वरकों का उपयोग कम करने और प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ने की अपील का उद्देश्य विदेशी देशों पर निर्भरता कम करना और कीमती विदेशी मुद्रा बचाना है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि खाड़ी युद्ध की इस अवधि के दौरान, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 38 अरब अमेरिकी डॉलर कम हो गया है, और हमारा भंडार 27 फरवरी को 728.5 अरब अमेरिकी डॉलर से घटकर 12 मई, 2026 तक 690.7 अरब अमेरिकी डॉलर रह गया है।

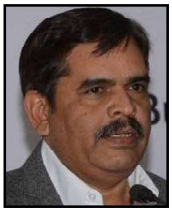

प्रधानमंत्री की लोकप्रियता और लोगों द्वारा समस्या की गंभीरता को समझने की बात को ध्यान में रखते हुए, यदि हम इन आयातों को कम करके और खुद पर संयम रखकर विदेशी मुद्रा के खर्च को केवल 10 प्रतिशत भी कम कर पाते हैं, तो हम लगभग 30 अरब अमेरिकी डॉलर बचा सकते हैं, और रुपये के मूल्य को बचाने में मदद कर सकते हैं।
– डॉ. अश्वनी महाजन

आमतौर पर, रुपये की स्थिरता के बारे में दो तरह के विचार हैं। एक वर्ग मानता है कि विनिमय दर, बाज़ार द्वारा निर्धारित एक मूल्य से ज़्यादा कुछ नहीं है; और अगर मुद्रा का मूल्य गिरता भी है, तो भी किसी को चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आयात और निर्यात

विनिमय दर के अनुसार अपने आप समायोजित हो जाएँगे। उनका मानना है कि घरेलू मुद्रा के मूल्य में गिरावट आयात को हतोत्साहित और निर्यात को प्रोत्साहित कर सकती है। भारतीय रुपये के बारे में, कभी–कभी उनका मानना होता है कि इसका मूल्य ज़रूरत से ज़्यादा है, और इसलिए यदि रिज़र्व बैंक रुपये में किसी भी गिरावट को रोकने के लिए हस्तक्षेप करता है, तो इससे अर्थव्यवस्था को नुकसान होगा, क्योंकि ऐसा करने से आयात को बढ़ावा मिलेगा और निर्यात हतोत्साहित होगा।

दूसरा वर्ग रूपये की मजबूती में विश्वास रखता है। उन्हें लगता है कि केवल एक मज़बूत रुपया ही मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में मदद कर सकता है, और ऋण सेवाओं (मूलधन और ब्याज की अदायगी), लाभांश, रॉयल्टी, वेतन और अन्य आय हस्तांतरणों के कारण होने वाले विदेशी मुद्रा के बहिर्प्रवाह को नियंत्रण में रख सकता है।

सत्ता की बागडोर संभालने से पहले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यह तर्क देते रहे हैं कि पिछली सरकार की गलत नीतियों के कारण ही रुपये में गिरावट आई है, और इसलिए केवल सही नीतियों द्वारा ही समूह ही रुपये के अवमूल्यन को रोका जा सकता है।

हालांकि, रुपए का मूल्य हमेशा से चर्चा का विषय रहा है, लेकिन हमें यह समझना होगा कि सरकार चाहे कितनी भी मज़बूत क्यों न हो, वह कृत्रिम रूप से विनिमय दर तय नहीं कर सकती और न ही इसे बढ़ाने में मदद कर सकती है। विनिमय दर विदेशी मुद्राओं (जैसे डॉलर) की मांग और आपूर्ति द्वारा तय होती है। जहां विदेशी मुद्रा की मांग वस्तुओं और सेवाओं के आयात, ऋण चुकाने (अतीत में लिए गए ऋणों के मूलधन और ब्याज की वापसी), लाभांश, रॉयल्टी, तकनीकी शुल्क, वेतन और अन्य आय हस्तांतरण के कारण

रुपए का मूल्य हमेशा से चर्चा का विषय रहा है, लेकिन हमें यह समझना होगा कि सरकार चाहे कितनी भी मज़बूत क्यों न हो, वह कृत्रिम रूप से विनिमय दर तय नहीं कर सकती और न ही इसे बढ़ाने में मदद कर सकती है। विनिमय दर विदेशी मुद्राओं (जैसे डॉलर) की मांग और आपूर्ति द्वारा तय होती है।

होती है; वहीं विदेशी मुद्रा की आपूर्ति वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के शुद्ध प्रवाह, और विदेशों से प्राप्त विदेशी पोर्टफोलियो निवेश आदि से होती है। यदि सरकार रुपए को मज़बूत बनाना चाहती है, तो वह प्रशासनिक रूप से विनिमय दर तय करके कृत्रिम रूप से ऐसा हासिल नहीं कर सकती। इसमें कोई संदेह नहीं है कि कभी–कभी भारतीय रिज़र्व बैंक बाज़ार में हस्तक्षेप करता है और बाज़ार में विदेशी मुद्रा की आपूर्ति बढ़ाकर रुपए में अल्पकालिक उतार–चढ़ाव को रोकने की कोशिश करता है; लेकिन यदि चालू खाते पर भुगतान संतुलन में लगातार घाटे के कारण रुपए का मूल्य गिरता है, तो लंबे समय में इस प्रकार के हस्तक्षेप का प्रभाव बहुत सीमित होता है। रुपए के मूल्य को कृत्रिम रूप से बनाए रखने के लिए आरबीआई को अपने विदेशी मुद्रा भंडार से लगातार अधिक से अधिक डॉलर बाज़ार में डालने पड़ते हैं। इसलिए, यह खतरा बना रहता है कि यदि रिज़र्व बैंक विदेशी मुद्रा बाज़ार में हस्तक्षेप करना जारी रखता है, तो उसका विदेशी मुद्रा भंडार समाप्त हो सकता है। अतः, रुपए का मूल्य सुधारने के लिए, हमें इस घाटे के लिए ज़िम्मेदार मूल कारणों को ठीक करने की आवश्यकता है।

हाल के वर्षों में भारत में रुपए के मूल्य पर विचार करें, तो हम पाते हैं कि 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 के बीच रुपए का मूल्य अपेक्षाकृत स्थिर रहा और इस अवधि के दौरान इसमें मात्र 2.3 प्रतिशत की गिरावट आई। लेकिन 1 अप्रैल 2025 से अब तक, एक साल से कुछ अधिक समय में ही रुपए का मूल्य 11.7 प्रतिशत गिर गया है। इस अवधि के दौरान सबसे बड़ी

गिरावट 27 फरवरी 2026 को युद्ध शुरू होने से लेकर 13 मई 2026 तक के समय में हुई। मात्र ढाई महीने की छोटी सी अवधि में ही रुपए का मूल्य काफी गिर गया, 4.4 प्रतिशत की गिरावट के साथ, यह 91.1 रुपए प्रति अमेरिकी डॉलर से गिरकर 95.5 रुपए प्रति अमेरिकी डॉलर पर पहुँच गया। इससे नीति निर्माताओं में बड़ी चिंता व्याप्त है। हम समझते हैं कि रुपये की कीमत में गिरावट का मुख्य कारण कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें हैं, जिससे व्यापार घाटा तेज़ी से बढ़ रहा है, और विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा शेयर बाज़ारों में भारी बिकवाली भी जारी है।

प्रधानमंत्री की नागरिकों से की गई अपील, कि वे सार्वजनिक परिवहन और इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग करके पेट्रोल और डीजल की खपत कम करें; सोना खरीदना टाल दें; विदेश यात्रा को कम से कम एक साल के लिए स्थगित कर दें; खाना पकाने के तेल की खपत कम करें और रासायनिक उर्वरकों से बचते हुए प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ें, एक समझदारी भरी सलाह है, जो हमारी कीमती विदेशी मुद्रा को बचाने और रुपये को और अधिक गिरने से बचाने में मदद करेगी।

हालाँकि, हमें उम्मीद है कि युद्ध खत्म होने पर रुपया स्थिर हो जाएगा, लेकिन रुपये की समस्या का दीर्घकालिक समाधान देश के भुगतान संतुलन को ठीक करके ही निकाला जा सकता है। भुगतान संतुलन का पहला हिस्सा वस्तुओं के व्यापार संतुलन से आता है। हम देखते हैं कि पिछले कुछ सालों में, वस्तुओं के आयात में बढ़ोतरी और निर्यात में सुस्ती का रुझान काफी बढ़ा है। लेकिन साल 2025–26 के दौरान, आयात में अचानक तेज़ी देखी गई, जबकि निर्यात लगभग स्थिर रहा; इसके परिणामस्वरूप वस्तु व्यापार घाटा 50 अरब अमेरिकी डॉलर बढ़ गया, और 2024–25 के 283.5 अरब अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2025–26 में 333.2 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गया। हालाँकि, घाटे में हुई इस भारी बढ़ोतरी की कुछ हद तक भरपाई सेवाओं के व्यापार में हुए अतिरिक्त अतिरेक से हो गई; यह अतिरेक 2024–25 के 188.8 अरब अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2025–26 में 213.9 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गया, यानी इसमें 25 अरब डॉलर की बढ़ोतरी हुई। अगर हम भारत द्वारा आयात किए जाने वाले मुख्य सामानों पर नज़र डालें, तो उनमें पेट्रोलियम उत्पाद, सोना, खाने का तेल, रासायनिक उर्वरक आदि शामिल हैं। विदेशी मुद्रा के बाहर जाने का एक और मुख्य कारण भारतीयों द्वारा की जाने वाली विदेश यात्रायों पर किए जाने वाला खर्च है। माल के आयात में लगातार और तेज़ी से बढ़ोतरी होना, और निर्यात का स्थिर रहना, यह अर्थव्यवस्था के लिए आम तौर पर, और रुपये की कीमत के लिए विशेष रूप से, एक खतरे की घंटी है। विदेश यात्राओं और पढ़ाई के लिए विदेश जाने वाले भारतीय छात्रों की वजह से विदेशी मुद्रा की माँग भी हाल के वर्षों में लगातार बढ़ रही है।

अनुमान है कि 2025–26 में कच्चे तेल के आयात का बिल लगभग 135 अरब अमेरिकी डॉलर होने की उम्मीद है; सोने के आयात, रासायनिक उर्वरकों और खाने के तेल के बिल पर विदेशी मुद्रा का अपेक्षित खर्च क्रमशः 72 अरब अमेरिकी डॉलर, 14 से 18 अरब अमेरिकी डॉलर और 19 अरब अमेरिकी डॉलर होने का अनुमान है। विदेश जाने वाले भारतीय यात्रियों और विदेश में पढ़ाई करने जाने वाले भारतीय छात्रों द्वारा विदेशी मुद्रा पर किया जाने वाला खर्च क्रमशः लगभग 30–35 अरब अमेरिकी डॉलर और 15–20 अरब अमेरिकी डॉलर है।

हम भली–भांति समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री की नागरिकों से की गई अपील, कि वे सार्वजनिक परिवहन और इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग करके पेट्रोल और डीजल की खपत कम करें; सोना खरीदना टाल दें; विदेश यात्रा को कम से कम एक साल के लिए स्थगित कर दें; खाना पकाने के तेल की खपत कम करें और रासायनिक उर्वरकों से बचते हुए प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ें, एक समझदारी भरी सलाह है, जो हमारी कीमती विदेशी मुद्रा को बचाने और रुपये को और अधिक गिरने से बचाने में मदद करेगी।

वैश्विक संघर्षों, बाधित मूल्य श्रृंखलाओं और हमारे विदेशी मुद्रा भंडार के खत्म होने के खतरे के कारण लगातार गिरते रुपये की समस्या की गंभीरता को देखते हुए, देश के हितों की रक्षा के लिए राष्ट्र को संकीर्ण राजनीतिक विमर्शों से ऊपर उठकर तेजी से कदम उठाने होंगे। प्रधानमंत्री की लोकप्रियता और लोगों द्वारा समस्या की गंभीरता को समझने की बात को ध्यान में रखते हुए, यदि हम इन आयातों को कम करके और खुद पर संयम रखकर विदेशी मुद्रा के खर्च को केवल 10 प्रतिशत भी कम कर पाते हैं, तो हम लगभग 30 अरब अमेरिकी डॉलर बचा सकते हैं, और रुपये के मूल्य को बचाने में मदद कर सकते हैं। ❑❑

ईरान-अमेरिका युद्ध और भारत की ऊर्जा-आर्थिक सुरक्षा

विश्व पिछले कई वर्षों से भू राजनैतिक संकट से गुजर रहा है। वर्ष 2008 के अमेरिकी वित्तीय संकट के बाद जिस तरह डालर प्रिंट करके मुद्रा आपूर्ति को बढ़ाया गया, उससे मौद्रिक जगत में असंतुलन की स्थिति पैदा हुई और अमेरिकी ऋण अप्रत्यासित ढंग से बढ़ा जो कोविड–2020 की अकास्मिक समस्या की वजह एक नई आर्थिक तंगी के कारण अमेरिकन अर्थव्यवस्था में एक नासूर बन गया है। मूल समस्या अमेरिका के ऋण की है जो लगभग 40 ट्रिलियन डॉलर है और जिस पर सालाना 1 ट्रिलियन डालर से ज्यादा ब्याज का भुगतान करना पड़ता है। अमेरिकी डॉलर के रिजर्व करेंसी होने की वजह से व्यापार घाटा एक आवश्यक बुराई है जिससे अमेरिका बाहर निकलना चाहता है। दूसरी ओर विश्व के ज्यादातर देश अमेरिकन बांड में अपना विनियोजन घटाना चाहते हैं। विश्व में एक नई सर्वमान्य वित्तीय व्यवस्था बने, यह एक बड़ी चुनौती है और 1944 के ब्रिटन वुड सिस्टम से निकलने की प्रक्रिया का ही अप्रत्यक्ष रूप से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प की छटपटाहट का कारण है।

वर्ष 1971 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन ने डालर के अंतरराष्ट्रीय करेंसी के गोल्ड स्टैण्डर्ड से उसका संबंध विच्छेद करके पेट्रो डालर द्वारा एक अवांछनीय व्यवस्था बनाई थी और वह व्यवस्था भी मध्य देशीय राष्ट्रों द्वारा 50 साल बाद अमान्य कर दी गई है जिसका भय अमेरिका को है, क्योंकि अब खाड़ी देश डालर के अलावा किसी भी अन्य विदेशी मुद्रा में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने के लिये स्वतंत्र हैं। अमेरिका वेनेजुएला के तेल भंडार पर कब्जा करने के बाद ईरान के तेल भंडार पर भी हुकूमत करना चाहता है जिसे ईरानी हुकूमत किसी भी हालत में स्वीकार नहीं कर सकती और ईरान अपनी आर्थिक एवं राजनैतिक प्रभुसत्ता को अक्षुण्ण रखना चाहता है।

प्रधानमंत्री की अपील का पालन करना सभी देशवासियों का कर्तव्य है। स्वदेशी वस्तुओं को अपनाना तथा स्थानीय उद्योग को प्रोत्साहन देना, वर्तमान समय की आवश्यकता है।

– डॉ. धनपतराम अग्रवाल

वर्तमान ईरान–अमेरिकी संघर्ष का मूल कारण अमेरिका की बिगड़ती हुई आर्थिक स्थिति है जिसे वह छद्म तरीके से वैश्विक संकट पैदा करके अपनी सामरिक ताक़त के बल पर अपना प्रभुत्व बनाये रखने के लिये ऐसा कर रहा है। समय आ गया है कि सारा विश्व एकजुट होकर अमेरिका की इस कुचाल को कुचल दे और एक नई आर्थिक व्यवस्था का मार्ग अपनाये जो नैतिकता और मानव धर्म पर आधारित हो। इस संदर्भ में वर्तमान होर्मुज़ जलडमरू मध्य अवरोध संबंधित विवेचन प्रासंगिक है।

ईरान–अमेरिका युद्ध 2026 और उसके परिणामस्वरूप उत्पन्न होर्मुज़ जलडमरू मध्य संकट ने यह सिद्ध कर दिया कि 21वीं सदी की वैश्विक राजनीति में ऊर्जा केवल व्यापारिक वस्तु नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक स्थिरता और रणनीतिक स्वायत्तता का केंद्रीय आधार बन चुकी है। फरवरी 2026 में अमेरिका और इज़राइल द्वारा ईरान पर संयुक्त सैन्य कार्रवाई, उसके बाद ईरान द्वारा होर्मुज़ जलडमरू मध्य को बंद घोषित करना, और वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला में आयी अभूतपूर्व बाधा ने विश्व अर्थव्यवस्था को हिला दिया। इस पूरे संकट का भारत पर व्यापक प्रभाव पड़ा – ऊर्जा, कृषि, उद्योग, मुद्रा, विदेश नीति और सामरिक अवसंरचना – सभी क्षेत्र इससे प्रभावित हुए।

प्रस्तुत लेख भारत की ऊर्जा निर्भरता, आर्थिक प्रभाव, रणनीतिक चुनौतियों और भविष्य की नीति दिशा का समग्र विश्लेषण प्रस्तुत करता है। इसमें ऊर्जा संकट, एलएनजी और एलपीजी आपूर्ति, मुद्रा एवं मुद्रास्फीति, कृषि, चाबहार बंदरगाह, रणनीतिक स्वायत्तता तथा विकसित भारत@2047 के संदर्भ में भारत की दीर्घकालिक रणनीतिक आवश्यकताओं का अध्ययन किया गया है।

होर्मुज़ जलडमरू मध्य विश्व ऊर्जा व्यापार का सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है। विश्व के लगभग 25 प्रतिशत समुद्री तेल व्यापार और लगभग 20 प्रतिशत एलएनजी आपूर्ति इसी मार्ग से गुजरती है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने इसे "वैश्विक तेल बाज़ार के इतिहास की सबसे बड़ी आपूर्ति बाधा" बताया।

युद्ध का प्रारंभ और वैश्विक ऊर्जा संकट

28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इज़राइल ने ईरान के परमाणु एवं सैन्य ठिकानों पर संयुक्त हमला किया। इस हमले में ईरान के सर्वोच्च नेता अली ख़ामेनेई की मृत्यु की खबर ने पूरे पश्चिम एशिया को अस्थिर कर दिया। इसके तुरंत बाद ईरान ने होर्मुज़ जलडमरू मध्य को बंद घोषित कर दिया।

होर्मुज़ जलडमरू मध्य विश्व ऊर्जा व्यापार का सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है। विश्व के लगभग 25 प्रतिशत समुद्री तेल व्यापार और लगभग 20 प्रतिशत एलएनजी (लिक्विड नेचुरल गैस) आपूर्ति इसी मार्ग से गुजरती है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (आईईए) ने इसे "वैश्विक तेल बाज़ार के इतिहास की सबसे बड़ी आपूर्ति बाधा" बताया। ब्रेंट कच्चा तेल (क्रूड ऑयल) की कीमतें तेजी से बढ़ीं और वैश्विक वित्तीय बाजारों में भय एवं अनिश्चितता फैल गई।

भारत जैसे आयात–निर्भर देशों के लिए यह संकट अत्यंत गंभीर था। भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था अवश्य है, किंतु उसकी ऊर्जा संरचना अभी भी बाहरी आयातों पर अत्यधिक निर्भर है। यही कारण है कि यह संकट केवल अंतरराष्ट्रीय राजनीति तक सीमित नहीं रहा, बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था और आम नागरिक के जीवन पर सीधा प्रभाव डालने लगा।

भारत की ऊर्जा निर्भरता – एक संरचनात्मक चुनौती

भारत की ऊर्जा संरचना में मध्य पूर्व की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत की लगभग 90–91 प्रतिशत एलपीजी (LPG) आपूर्ति, लगभग 50 प्रतिशत एलएनजी (LNG) आयात, लगभग 60 प्रतिशत कच्चा तेल तथा उर्वरक उद्योग हेतु आवश्यक बड़ी मात्रा में यूरिया और फॉस्फेट, मध्य पूर्व और होर्मुज़ मार्ग पर निर्भर हैं।

जैसे ही होर्मुज़ मार्ग बाधित हुआ, भारत में एलपीजी संकट शुरू हो गया। घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में अचानक वृद्धि हुई। कई क्षेत्रों में गैस की कृत्रिम कमी और काला बाज़ार सक्रिय हो गया। कुछ स्थानों पर सिलेंडर के दाम 4000 रू. तक पहुँचने की खबरें भी सामने आईं।

यह स्थिति केवल घरेलू उपभोक्ताओं तक सीमित नहीं रही। होटल, रेस्टोरेंट, छोटे उद्योग और परिवहन क्षेत्र भी प्रभावित हुए। गुजरात की सिरेमिक उद्योग में उत्पादन घटा, जबकि महानगरों में रेस्टोरेंट ने सीमित संचालन शुरू किया।

ऊर्जा संकट के इस दौर ने भारत की सबसे बड़ी कमजोरी को उजागर किया – भारत की "ऊर्जा आत्मनिर्भरता" अभी भी अधूरी है।

रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार और चीन–भारत तुलना

इस संकट ने रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार (Strategic Petroleum Reserve-SPR) के महत्व को भी उजागर किया। भारत के पास केवल लगभग 30 दिनों

तेल आयात बिल में वृद्धि का सीधा प्रभाव भारत के चालू खाता घाटा पर पड़ा। अधिक डॉलर भुगतान के कारण रुपया कमजोर होने लगा। अभी 96–97 रूपये प्रति डॉलर तक अवमूल्यन हो चुका है।

का रणनीतिक तेल भंडार था, जबकि चीन के पास 3–4 महीनों का विशाल भंडारण उपलब्ध था।

यह अंतर केवल आर्थिक क्षमता का नहीं बल्कि रणनीतिक तैयारी का संकेत है। यदि होर्मुज़ संकट लंबा चलता, तो भारत को निम्नलिखित चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, जो अभी भी अनिश्चित है। कभी युद्ध के बंद, तो कभी चालू रहने की बात बनी रहती है। तेल टेंकर के आवागमन पर अंतरिम रूप से अवरोध बना हुआ है, जो एक खतरा है।

- पेट्रोल और डीज़ल राशनिंग,
- बिजली उत्पादन में कमी,
- औद्योगिक उत्पादन में गिरावट,
- सार्वजनिक परिवहन पर दबाव तथा
- व्यापक मुद्रास्फीति।

रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार किसी भी आधुनिक राष्ट्र की "ऊर्जा रक्षा प्रणाली" का हिस्सा है। जैसे सैन्य रक्षा के लिए हथियार आवश्यक हैं, वैसे ही आर्थिक सुरक्षा के लिए ऊर्जा भंडार आवश्यक हैं।

एलएनजी संकट, उर्वरक उद्योग और कृषि पर प्रभाव

भारत का उर्वरक उद्योग प्राकृतिक गैस पर आधारित है। एलएनजी आपूर्ति बाधित होने से उर्वरक संयंत्र प्रभावित हुए और कई संयंत्रों को अपनी क्षमता कम करनी पड़ी।

भारत के कई यूरिया और फॉस्फेट इम्पोर्टस गल्फ क्षेत्र से आते हैं। जब आपूर्ति बाधित हुई, तब कृषि क्षेत्र पर दबाव बढ़ने लगा। इसका प्रभाव केवल खाद की कीमतों तक सीमित नहीं था। यदि यह संकट लंबा चलता, तो –

- खाद्य उत्पादन प्रभावित होता,
- किसानों की लागत बढ़ती,
- खाद्य मुद्रास्फीति बढ़ती, तथा
- ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर गंभीर दबाव पड़ता।

भारत की खाद्य सुरक्षा और ऊर्जा सुरक्षा वास्तव में एक–दूसरे से जुड़ी हुई हैं। ऊर्जा संकट अंततः कृषि संकट में परिवर्तित हो सकता है।

मुद्रा, वित्तीय स्थिरता और भारतीय अर्थव्यवस्था

तेल आयात बिल में वृद्धि का सीधा प्रभाव भारत के चालू खाता घाटा (Current Account Deficit-CAD) पर पड़ा। अधिक डॉलर भुगतान के कारण रुपया कमजोर होने लगा। अभी 96–97 रूपये प्रति डॉलर तक अवमूल्यन हो चुका है।

रुपये की कमजोरी का प्रभाव कई स्तरों पर पड़ता है –

1. आयातित महँगाई बढ़ती है।
2. पेट्रोल–डीज़ल महँगा होता है।
3. औद्योगिक उत्पादन लागत बढ़ती है।
4. विदेशी ऋण महँगा होता है।
5. आम उपभोक्ता पर महँगाई का दबाव बढ़ता है।

यदि संकट और गहरा होता है, तो आरबीआई को ब्याज दरों, विदेशी मुद्रा हस्तक्षेप और पूँजी नियंत्रण जैसे कदम उठाने पड़ सकते है।

हालाँकि संयुक्त राष्ट्र ने मई 2026 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 6.4 प्रतिशत रहने का अनुमान दिया और भारत को विश्व की सबसे तेज़ बड़ी अर्थव्यवस्था बताया, फिर भी यह संकट स्पष्ट संकेत देता है कि केवल जीडीपी ग्रोथ पर्याप्त नहीं है। ऊर्जा सुरक्षा कमजोर होने पर आर्थिक विकास अस्थिर हो सकता है।

आईएमएफ की नई रिपोर्ट में भारत की अर्थव्यवस्था को चौथी बड़ी आर्थिक शक्ति से घटाकर छठवीं स्थिति में पहुंचने का अनुमान लगाया है। जापान चौथी और इंग्लैंड पांचवीं तथा भारत छठी आर्थिक अवस्था में पहुंच गया है।

चाबहार पोर्ट और भारत की कनेक्टिविटी रणनीति

भारत ने ईरान के चाबहार बंदरगाह को मध्य एशिया और अफ़गानिस्तान तक पहुँचने के वैकल्पिक मार्ग के रूप में विकसित किया था। यह परियोजना भारत की सामरिक कनेक्टिविटी रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा थी। लेकिन अमेरिकी प्रतिबंधों और प्रतिबंधों में छूट समाप्त होने के बाद भारत की यह रणनीति कमजोर पड़ गई।

इसका प्रभाव केवल व्यापार तक सीमित नहीं था। चाबहार पोर्ट भारत के लिए –

- पाकिस्तान को दरकिनार करने का मार्ग,
- मध्य एशिया तक पहुँच,
- अफ़गानिस्तान में रणनीतिक प्रभाव, तथा
- अंतर्राष्ट्रीय उत्तर–दक्षिण परिवहन गलियारा (आईएनएसटीसी) का हिस्सा था।

इस संकट ने यह स्पष्ट कर दिया कि भारत की रणनीतिक परियोजनाएँ अभी भी वैश्विक शक्ति संतुलन और अमेरिकी प्रतिबंध व्यवस्था से प्रभावित हो सकती हैं।

रणनीतिक स्वायत्तता और भारत की विदेश नीति

ईरान–अमेरिका युद्ध 2026 ने भारत की रणनीतिक स्वायत्तता नीति की कठिन परीक्षा ली। भारत के अमेरिका और इज़राइल से बढ़ते सामरिक संबंध हैं, वहीं दूसरी ओर ऊर्जा सुरक्षा के लिए ईरान, सऊदी अरब, यूएई और अन्य खाड़ी (गल्फ) देशों के साथ संतुलन बनाए रखना भी अनिवार्य है।

इस संकट ने यह स्पष्ट कर दिया कि भविष्य की विदेश नीति केवल "गुटनिरपेक्षता" नहीं बल्कि "रणनीतिक संतुलन के साथ बहु–संरेखण" पर आधारित होनी चाहिए।

भारत को –

- अमेरिका के साथ तकनीकी एवं रक्षा सहयोग,
- रूस के साथ ऊर्जा साझेदारी,
- ईरान के साथ कनेक्टिविटी तथा
- खाड़ी देशों के साथ ऊर्जा एवं प्रवासी संबंध,

इन सभी को संतुलित करना होगा। यह एक जटिल लेकिन अनिवार्य कूटनीतिक संतुलन है।

खाड़ी प्रवासी भारतीय और सामाजिक प्रभाव

खाड़ी देशों में कार्यरत भारतीय प्रवासी भारत की अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। भारत को प्रतिवर्ष लगभग 135 अरब डालर का प्रेषण प्राप्त होता है, जिसका बड़ा हिस्सा खाड़ी क्षेत्र से आता है। यदि पश्चिम एशिया में दीर्घकालिक अस्थिरता उत्पन्न होती, तो –

- लाखों भारतीयों की नौकरियाँ प्रभावित हो सकती थीं,
- प्रेषण प्रवाह घट सकता था तथा
- भारत के कई राज्यों की ग्रामीण अर्थव्यवस्था प्रभावित हो सकती थी।

इसलिए भारत को केवल ऊर्जा कूटनीति ही नहीं, बल्कि प्रवासी आकस्मिकता नीति भी विकसित करनी होगी।

भारत के लिए नीति–संदेश और भविष्य की रणनीति

यह संकट भारत के लिए एक "राष्ट्रीय रणनीतिक चेतावनी" है। भारत को निम्नलिखित क्षेत्रों में दीर्घकालिक सुधार करने होंगे:

(1) रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार (एसपीआर) विस्तार – भारत को अपना एसपीआर कम से कम 90 दिनों तक बढ़ाना चाहिए।

(2) ऊर्जा विविधीकरण – रूस, अफ्रीका, लातिन अमरीकी देशों के साथ–साथ अमरीका से दीर्घकालिक तेल एवं गैस समझौते आवश्यक हैं।

(3) नवीकरणीय ऊर्जा और गैस अवसंरचना – घरेलू गैस पाईपलाईन नेटवर्क, नवीकरणीय ऊर्जा, ग्रीन हाइड्रोजन और न्यूक्लियर ऊर्जा पर तेज़ निवेश आवश्यक है।

(4) चाबहार और आईएनएसटीसी को प्राथमिकता – भारत को आईएनएसटीसी कॉरिडोर को वैकल्पिक व्यापारिक धुरी के रूप में विकसित करना चाहिए।

(5) उर्वरक और एलएनजी आत्मनिर्भरता – घरेलू उर्वरक एवं एलएनजी क्षमता बढ़ानी होगी।

(6) ऊर्जा कूटनीति – ऊर्जा कूटनीति को विदेश नीति का केंद्रीय तत्व बनाना होगा।

(7) प्रवासी नीति – खाड़ी देशों में कार्यरत भारतीयों के लिए आपातकालीन निकासी और रोजगार पुनर्एकीकरण तैयार करनी होगी।

इन चुनौतियों से निपटने के लिए भारत के प्रधानमंत्री ने देश के नागरिकों से अपील की है कि वे विदेशी मुद्रा के खर्च में कटौती लायें तथा पेट्रोल–डीजल के उपभोग में संयम से काम ले। सोने (गोल्ड) की खरीद को एक वर्ष के लिए बंद करें। केमिकल खाद के स्थान पर देशी खाद का व्यवहार करें।

प्रधानमंत्री की अपील का पालन करना सभी देशवासियों का कर्तव्य है। स्वदेशी वस्तुओं को अपनाना तथा स्थानीय उद्योग को प्रोत्साहन देना, वर्तमान समय की आवश्यकता है।

निष्कर्ष

विकसित भारत के लिए ऊर्जा सुरक्षा अनिवार्य है। होर्मुज़ संकट केवल तेल और गैस की आपूर्ति का संकट नहीं है। यह भारत के लिए एक व्यापक रणनीतिक चेतावनी है।

इस संकट ने स्पष्ट कर दिया कि' आर्थिक शक्ति, ऊर्जा सुरक्षा, कूटनीतिक संतुलन, रणनीतिक अवसंरचना तथा राष्ट्रीय सुरक्षा, अब एक–दूसरे से अलग नहीं हैं।

यदि भारत को वास्तव में "विकसित भारत@2047" का लक्ष्य प्राप्त करना है, तो उसे ऊर्जा आत्मनिर्भरता, सामरिक भंडारण, विविध आपूर्ति शृंखलाएं, नवीकरणीय बुनियादी ढांचा और संतुलित कूटनीति को राष्ट्रीय विकास रणनीति का केंद्रीय हिस्सा बनाना होगा।

21वीं सदी में वही राष्ट्र दीर्घकालिक आर्थिक शक्ति बनेंगे, जो ऊर्जा सुरक्षा को केवल आर्थिक विषय नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मूल स्तंभ के रूप में देखेंगे। भारत के लिए होर्मुज़ संकट इसी ऐतिहासिक परिवर्तन का संकेत है। ❑❑

स्रोत

1. Wikipedia: 2026 Iran War; Economic Impact; India in 2026 Iran War; Fuel Crisis; Strait of Hormuz Crisis
2. Britannica: 2026 Iran War - Comprehensive Event Coverage
3. House of Commons Library: US-Iran Ceasefire and Nuclear Talks 2026
4. CNBC: India-China Competition for Russian Oil Amid Hormuz Disruption
5. Anand Rathi PMS: US-Iran Conflict 2026 - India Sectoral Impact Analysis
6. US Congress CRS: Iran Conflict and the Strait of Hormuz - Energy Implications
7. Al Jazeera Centre for Studies: Walking a Tightrope - Iran-US Confrontation Scenarios
8. UN World Economic Situation & Prospects (Mid-Year 2026) - India Growth 6.4%

वर्तमान ऊर्जा संकट के दौर में आर्थिक संयम की जरुरत

आज पूरा विश्व अनेक प्रकार के संकटों से गुजर रहा है। कहीं युद्ध चल रहे हैं, कहीं आर्थिक मंदी का खतरा है, कहीं महंगाई बढ़ रही है और कहीं ऊर्जा संकट गहराता जा रहा है। भारत भी इन वैश्विक परिस्थितियों से अछूता नहीं है। ऐसे समय में देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देशवासियों को "बचत, संयम और आत्मनिर्भरता" का संदेश दिया है। यह संदेश केवल व्यक्तिगत जीवन के लिए नहीं, बल्कि राष्ट्र की आर्थिक सुरक्षा, विदेशी मुद्रा भंडार और ऊर्जा आत्मनिर्भरता से भी जुड़ा हुआ है।

हॉर्मुज़ जलडमरूमध्य और वर्तमान संकट

आज हॉर्मुज़ जलडमरूमध्य विश्व की सबसे महत्वपूर्ण सामरिक जगहों में से एक है। यह वह समुद्री मार्ग है जहाँ से विश्व का लगभग 20 प्रतिशत तेल और बड़ी मात्रा में गैस गुजरती है। भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं का बड़ा हिस्सा पश्चिम एशिया से आयात करता है। यदि हॉर्मुज़ क्षेत्र में युद्ध, तनाव या संघर्ष बढ़ता है, तो तेल और गैस की आपूर्ति प्रभावित हो सकती है। इससे पेट्रोल, डीजल और एल.पी.जी. की कीमतें तेजी से बढ़ सकती हैं तथा भारत का आयात बिल भी बढ़ जाएगा। ऐसी स्थिति में देश की विदेशी मुद्रा पर भारी दबाव पड़ता है। इसलिए प्रधानमंत्री का "बचत और आत्मनिर्भरता" का संदेश आज और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है।

विदेशी मुद्रा भंडार का महत्व

विदेशी मुद्रा भंडार वह धनराशि होती है जिसे कोई देश विदेशी मुद्राओं और सोने के रूप में सुरक्षित रखता है। यह आर्थिक संकट के समय देश की सुरक्षा कवच की तरह कार्य करता है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार लगभग 650–700 अरब अमेरिकी डॉलर के आसपास रहा है, लेकिन भारत अभी भी कच्चे तेल, एल.पी.जी., खाद्य तेल और सोने के आयात पर काफी निर्भर है। यदि वैश्विक संकट बढ़े और आयात महँगा हो जाए, तो विदेशी मुद्रा भंडार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बचत मंत्र केवल आर्थिक नीति नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण का मार्ग है। विदेशी मुद्रा भंडार जितना मजबूत होगा, भारत उतना ही आत्मनिर्भर, सुरक्षित और शक्तिशाली बनेगा।
– दुलीचंद कालीरमन

तेजी से प्रभावित हो सकता है। इसलिए अनावश्यक आयात कम करना राष्ट्रीय आवश्यकता बन गया है।

प्रधानमंत्री के बचत मंत्र

1. सोना खरीदने को कुछ समय टालना

भारत दुनिया के सबसे बड़े स्वर्ण आयातक देशों में से एक है। भारत हर वर्ष लगभग 700 से 900 टन सोना आयात करता है, जिस पर 40 से 60 अरब अमेरिकी डॉलर तक खर्च हो जाते हैं।

यह विदेशी मुद्रा भंडार पर भारी बोझ डालता है। यदि देशवासी कुछ समय के लिए अनावश्यक सोना खरीदना टाल दें, तो अरबों डॉलर की बचत हो सकती है। इससे विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव कम होगा। यह राशि देश के विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा में उपयोग की जा सकती है।

संकट के समय अनावश्यक सोना खरीदना कम करना देशहित में आवश्यक कदम हो सकता है। इससे विदेशी मुद्रा की बचत होगी और आर्थिक स्थिरता मजबूत होगी।

2. विदेश यात्राओं में संयम

विदेश पर्यटन पर भारतीय नागरिक हर वर्ष अरबों डॉलर खर्च करते हैं। यदि लोग अनावश्यक विदेश यात्राएँ कम करें और भारत के पर्यटन स्थलों को बढ़ावा दें, तो विदेशी मुद्रा देश में बचेगी तथा स्थानीय रोजगार को भी लाभ मिलेगा। इससे युवा पीढ़ी को अपनी जड़ों और संस्कृति से जुडने एवं समझने का भी अवसर मिलेगा।

3. खाद्य तेल की कम खपत

भारत खाद्य तेल का बड़ा आयातक देश है। इसका आयात बिल 1.61 लाख करोड़ का है। यदि परिवार खाने में तेल का उपयोग थोड़ा कम करें, तो इससे विदेशी मुद्रा की बचत होगी और लोगों का स्वास्थ्य भी बेहतर होगा।

देश के युवाओं को समझना होगा कि फिजूलखर्ची केवल व्यक्तिगत नहीं, बल्कि राष्ट्रीय नुकसान भी है। यदि युवा वर्ग सादगी, बचत और स्वदेशी को अपनाए, तो भारत आर्थिक रूप से और अधिक मजबूत बन सकता है।

4. जैविक और प्राकृतिक खेती

प्रधानमंत्री प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रहे हैं। रासायनिक खाद और कीटनाशकों के आयात पर भारी विदेशी मुद्रा खर्च होती है। जैविक खेती अपनाने से यह निर्भरता कम होगी तथा मिट्टी और पर्यावरण की रक्षा भी होगी। भारत कृषि प्रधान देश है, लेकिन आज भी रासायनिक उर्वरकों के लिए काफी हद तक विदेशों पर निर्भर है। यूरिया, डीएपी, पोटाश और अन्य उर्वरकों का बड़ा हिस्सा विदेशों से आयात किया जाता है। भारत हर वर्ष लगभग 15 से 20 अरब अमेरिकी डॉलर तक उर्वरकों और उनसे जुड़े कच्चे माल के आयात पर खर्च करता है। यह भुगतान विदेशी मुद्रा यानी डॉलर में किया जाता है।

जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में गैस और उर्वरकों की कीमतें बढ़ती हैं, तब भारत का आयात बिल और अधिक बढ़ जाता है। रूस–यूक्रेन युद्ध के बाद पूरी दुनिया में उर्वरकों की कीमतों में भारी वृद्धि देखी गई थी। यदि भारत जैविक और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देता है, तो रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम होगी और अरबों डॉलर की विदेशी मुद्रा बचाई जा सकती है।

5. पेट्रोल–डीजल की कम खपत और एल.पी.जी. के स्थान पर इंडक्शन चूल्हों का उपयोग

पश्चिम एशिया के संकट के कारण कच्चे तेल के दाम उच्चतम स्तर पर पहुँच गए हैं। लगातार सप्लाई बाधित हो रही है। आने वाले काफी समय तक स्थिति सामान्य होने की उम्मीद नहीं है। इसलिए विदेशी मुद्रा भण्डार पर अतिरिक्त बोझ और अनिश्चितता के वातावरण में जहाँ तक संभव हो हमें सार्वजनिक परिवहन को अपनाना होगा या कार–पूलिंग जैसी व्यवस्था से पेट्रोल–डीजल की खपत को कम करना होगा। भारत अपनी आवश्यकता का बड़ा हिस्सा एल.पी.जी. गैस विदेशों से आयात करता है। यदि हॉर्मुज़ क्षेत्र में संकट बढ़ता है, तो एल.पी.जी. की कीमतों में भी भारी वृद्धि हो सकती है।

ऐसी स्थिति में इंडक्शन चूल्हों का उपयोग एक महत्वपूर्ण विकल्प बन सकता है। यदि परिवार धीरे–धीरे एल. पी.जी. के स्थान पर इंडक्शन आधारित खाना पकाने की व्यवस्था अपनाएँ, तो गैस आयात पर निर्भरता कम होगी। भारत सौर और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसलिए बिजली आधारित खाना पकाने की व्यवस्था भविष्य के लिए अधिक सुरक्षित और टिकाऊ विकल्प बन सकती है।

युवाओं और समाज की भूमिका

देश के युवाओं को समझना होगा कि फिजूलखर्ची केवल व्यक्तिगत नहीं, बल्कि राष्ट्रीय नुकसान भी है। यदि युवा वर्ग सादगी, बचत और स्वदेशी को अपनाए, तो भारत आर्थिक रूप से और अधिक मजबूत बन सकता है। परिवारों को बच्चों को बचपन से बचत, अनुशासन और राष्ट्रहित की शिक्षा देनी चाहिए। वर्तमान वैश्विक संकट, विशेषकर हॉर्मुज़ जलडमरूमध्य में बढ़ता तनाव, हमें आत्मनिर्भर और जिम्मेदार बनने की चेतावनी देता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बचत मंत्र केवल आर्थिक नीति नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण का मार्ग है। विदेशी मुद्रा भंडार जितना मजबूत होगा, भारत उतना ही आत्मनिर्भर, सुरक्षित और शक्तिशाली बनेगा। ❑❑

महंगे दिन से निपटने का मंत्र है आत्मनिर्भरता

खाड़ी युद्ध के कारण महंगाई अब अपने देश भारत में भी अपना पैर पसारने लगी है। खुदरा और थोक दोनों स्तर पर महंगाई ऊंचाई की ओर जा रही है। थोक महंगाई 3.8 के स्तर से उठकर अब 8.6 का आंकड़ा छू चुकी है। जैसे तैसे रोज कमाने खाने वाले तो पहले से ही परेशान रहे हैं, हालिया बढ़ोतरी से उनकी दिक्कतें और बढ़ गई है। कामगारों को नियमित काम धंधा नहीं मिला तो उन पर दो जून की रोटी भी भारी पड़ सकती है। रोजमर्रा के समानों के मूल्य वृद्धि से खाते पीते मध्य वर्ग के पेशानी पर भी बल पड़ने लगा है। महंगाई के चारों तरफ से जकड़ने का सिलसिला अगर आगे भी बना रहता है तो आमजन का जीवन कठिन हो सकता है, लेकिन संयम के साथ आत्मनिर्भरता के रास्ते पर चलकर महंगाई की आंच को कम किया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी खरीदारी में संयम बरतने और स्वदेशी आत्मनिर्भरता की वकालत की है।

खाड़ी युद्ध के कारण दुनिया भर में चीजों के दाम बढ़े हैं। सभी देश हालात से निपटने और अपने नागरिकों में आपूर्ति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए इंतजाम भी कर रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री देश की जनता से खरीदारी और पर्यटन पर संयम बरतने की अपील खुद कर चुके है। अपने विदेश प्रवास के दौरान नीदरलैंड की धरती से उन्होंने भविष्यवाणी की है कि यह दशक आपदा का दशक है, आगे और भी कठिनाई आ सकती है। प्रधानमंत्री ने वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत के लिए स्वदेशी नवाचार को प्रमुखता देने की बात की है। रसोई गैस खाने का तेल डीजल पेट्रोल के उपयोग पर लगाम लगाने तथा सोने जैसे महंगे आयत वाली वस्तुओं की अनावश्यक खरीददारी पर रोक का मंत्र उपयोगी बताते हुए उन्होंने कहा है कि जहां तक संभव हो सके देश के नागरिकों को स्वदेशी विकल्पों को तलाशने के लिए आगे आना चाहिए।

भारत स्वभाव से एक स्वावलंबी आत्मनिर्भर देश रहा है। उम्मीद की जानी चाहिए कि वर्तमान समस्या से निपटने में भी भारत कामयाब होगा। आत्मनिर्भरता का मंत्र सहयोगी बनेगा। स्वावलंबी और आत्मनिर्भर भारत के बल पर भारतीय आकाश से महंगे दिन के कुहासे जरूर छंट जाएंगे।

– अनूप पांडे

प्रधानमंत्री की अपील का जमीनी असर हो रहा है। आम आदमी महंगे सोने की खरीदारी से लेकर तेल के प्रयोग में भी कटौती कर रहा है। उत्साही कार्यकर्ता बिना तेल के पुड़ी सब्जी बनाने के नए–नए नुस्खों का रील बनाकर सोशल मीडिया पर परोस रहे हैं। ऐसे ही एक उत्साही कार्यकर्ता है सोमदत्त जी वे भी वीडियो में तेल खाने के नुकसान गिना रहे हैं। उनकी तार्किक बातों का असर भी हुआ है उनके फॉलोअर इन दोनों बढ़ गए हैं।

भारत इंग्लैंड को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया था। करोना कि वैश्विक महामारी के के बाद अर्थव्यवस्था ऊपर की ओर उठ रही थी की तभी रूस यूक्रेन युद्ध और अब खाड़ी युद्ध में आपूर्ति श्रृंखला को ऐसा बाधित कर दिया है कि दुनिया भर में महंगाई तांडव मचा रही है। भारत सरकार अपने नागरिकों की चिंता करते हुए अभी बहुत हद तक महंगाई को रोक रखा है। खासकर पेट्रोल डीजल के दाम दुनिया भर में आसमान छू रहे हैं जबकि भारत सरकार ने मामूली बढ़ोतरी की ही इजाजत दी है।

सरकार ने डीजल और पेट्रोल की कीमतों में तीन रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। लेकिन इस मामूली बढ़ोतरी से ही देश की जनता के कान खड़े हो गए हैं। आमजन को यह लगने लगा है कि यह बढ़ोतरी केवल डीजल और पेट्रोल के दाम तक सीमित नहीं है

आने वाले दिनों में रोजाना प्रयोग आने वाली चीजों से लेकर घरों के मासिक खर्चे पर भी भारी बोझ बढ़ने वाला है जिसका असर रोजमर्रा की सेवाओं पर भी दिखाई देगा।

तेजी से बिकने वाले उपभोक्ता उत्पाद की बड़ी कंपनियों ने पहले ही लागत के दबाव को लेकर चिंता जताना शुरू कर दिया है। बिस्किट, स्नैक्स, नूडल्स, खाद्य तेल, पैकेट बंद फूड, पेय पदार्थ जैसे उत्पाद लॉजिस्टिक नेटवर्क पर बहुत अधिक निर्भर करते हैं। ऑपरेशनल मूल्य का 6 से 10 प्रतिशत हिस्सा लॉजिस्टिक में खर्च होता है, इसलिए डीजल पेट्रोल की ऊंची कीमतें खर्चों को बढ़ा देती हैं। इसलिए जाहिर है कि उनके दाम भी कभी भी किसी भी क्षण बढ़ाए जा सकते हैं।

दूध की कीमतों में पहले से ही लागत बढ़ोतरी के संकेत मिलते रहे हैं। इधर अमूल और मदर डेयरी ने दूध की कीमतों में दो रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी है जिसका कारण परिवहन और परिचालन खर्चों में बढ़ोतरी बताया गया है। अब दूध के दाम बढ़ने से दूध से बनने वाले उत्पाद दही, मक्खन, पनीर, चीज और आइसक्रीम के दाम में भी जल्दी ही वृद्धि देखने को मिल सकती है।

भारत में खाद्य आपूर्ति श्रृंखला काफी हद तक सड़क परिवहन पर निर्भर करती है। सब्जियां, फल, अनाज, दाल, पैकेट बंद फूड एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में खर्चा बढ़ जाता है। ऐसे में डीजल की बढ़ती लागत से माल ढुलाई शुल्क में भी वृद्धि होगी जिसे ग्राहकों पर डाल दिया जाएगा। अर्थशास्त्रियों का कहना है कि अगर तेल की कीमतें लंबे समय तक ऊपर उठी रहती है तो रसोई के बजट पर महंगाई का दबाव और अधिक बढ़ जाएगा।

महंगाई का बुरा असर देश के किसानों पर भी पड़ेगा क्योंकि किसान

मुख्य रूप से डीजल से चलने वाले उपकरणों पर निर्भर रहते हैं। ट्रैक्टर, सिंचाई पंप, कटाई मशीन डीजल की बढ़ती लागत के कारण महगे हो जाएंगे। किसान को खेत से अपना सामान बाजार तक पहुंचाने की भी लागत बढ़ जाएगी। तेल की महंगाई का सीधा असर ग्रामीण परिवारों पर पड़ने वाला है।

कोरियर कंपनियों और ऑनलाइन शॉपिंग कंपनियों का लॉजिस्टिक भी महंगा हो जाएगा। फ्यूल की बढ़ती कीमत आखिरी मील की डिलीवरी का खर्च बढ़ा देगी। इस बढ़ोतरी से डिलीवरी शुल्क में बढ़ोतरी और मिनिमम ऑर्डर प्राइस में बढ़ोतरी की संभावना बढ़ गई है।

तेल के दाम बढ़ने से परिवहन लागत में वृद्धि के साथ–साथ साबुन शैंपू डिटर्जेंट सहित तमाम तरह के घरेलू चीजों के दाम बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। कुल मिलाकर महंगाई ने इस समय अपना तेवर दिखाना शुरू कर दिया है। चूंकि यह दौर वैश्वीकरण का दौर है इसलिए पूरी दुनिया की तरह भारत में भी चीजों के दाम बढ़ रहे हैं। वैश्वीकरण के बाद आयात निर्यात के कठिन नियमों के कारण अधिकांश चीजों के मूल्य पर केवल उत्पादक कंपनियों का ही अधिकार है इसलिए भी महंगाई बढी है।

ऐसा नहीं है कि भारत के समक्ष महंगाई की समस्या पहली बार आ रही है। दुनिया में पहले भी कई बार महंगाई ने जीवन को कठिन बनाया, बहुत सारे देशों में जरूरी वस्तुओं के लिए भी हाहाकार मचाने की स्मृतियां हैं। लेकिन भारत अपने स्वदेशी विकल्पों के कारण हमेशा हर समस्या से बाहर आता रहा है। वर्ष 2008 की मंदी में भी भारत सही कुशल निकल आया था। करोना की महामारी से जब पूरी दुनिया हलकान थी भारत ने न सिर्फ अपने लिए टीका विकसित किया बल्कि अधिकांश देशों को समय से उचित इलाज मुहैया कराया। खाड़ी युद्ध के कारण दुनिया के समक्ष ऊर्जा संकट पैदा हुआ है। दुनिया भर के देश इससे निपटने के लिए रास्ता तलाश रहे हैं। भारत की सरकार ने भी नागरिकों की रक्षा सुरक्षा के लिए अनेक जरूरी कदम उठाए हैं। प्रधानमंत्री ने खुद देश की जनता से मिलजुल कर इस आपदा से निपटने की अपील की है। भारत स्वभाव से एक स्वावलंबी आत्मनिर्भर देश रहा है। उम्मीद की जानी चाहिए कि वर्तमान समस्या से निपटने में भी भारत कामयाब होगा। आत्मनिर्भरता का मंत्र सहयोगी बनेगा। स्वावलंबी और आत्मनिर्भर भारत के बल पर भारतीय आकाश से महंगे दिन के कुहासे जरूर छंट जाएंगे। ❑❑

(लेखक भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं)

वैश्विक चुनौतियों के मद्देनजर भारत को चाहिए नई तरकीब

कूटनीति में जब बात की तासीर बदलने लगे तो माना जाता है कि परदे के पीछे कोई नया जाल बुना जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति चिनफिंग की हालिया मुलाकात के बाद मीडिया में छपी तस्वीरों में जो बनावटी मुस्कान दिख रही है वह सबूत है की राजनीति में कुछ भी स्थाई नहीं होता, न तो नफरत और न ही प्रेम। यहां केवल सत्ता संघर्ष ही सर्व प्रमुख होता है। कुछ दिन पहले तक चीन को सबक सिखाने, 100 प्रतिशत तक टैरिफ लगाने और क्या–क्या अन्य आरोप लगाने वाले ट्रंप के बोल बदल गए और साझा समृद्धि की दुहाई देने लगे है। वहीं दूसरी तरफ महामारी करोना को 'चीनी वायरस' कहे जाने का दंश झेल चुके चिनफिंग ने 'मेक अमेरिका ग्रेट अगेन' के नारे पर कदमताल करने की रजामंदी दी है।

राजनीति में खासकर विश्व राजनीति में ह्रदय परिवर्तन के अनेक उदाहरण मौजूद हैं। लेकिन ताइवान के मुद्दे पर चीन और अमेरिका की तनातनी, एक दूसरे को देख लेने की धमकी के बीच अचानक बदले सुर के निहितार्थों को तलाशने के लिए हमें खाड़ी युद्ध से उपजे हालातों को ठीक से डिकोड करना होगा। इजरायल और ईरान के मध्य छिड़े युद्ध में जब अमेरिका कूदा तो उसे यह उम्मीद थी कि जिस तरह पलक झपकते वेनेजुएला का मामला फतह कर लिया, कुछ उसी अंदाज में एक–दो हफ्ते में सीमित सैन्य अभियान चलाकर बाजी मार लेगा। लेकिन वहां दाव उल्टा पड़ गया। जैसे–जैसे समय बीता, अमेरिका की बेचैनी बढ़ती जा रही है।

हम सभी जानते हैं कि अमेरिकी जनता सबसे पहले अपने खुद का हित चाहती है। जिस तरह वहां की सरकारें अमेरिका फर्स्ट का नारा लगती हैं, उसी तरह वहां की आबादी सारी सुख–सुविधाएं 'पहले मुझे' का गीत गाने की शौकीन रही है। इतिहास में जब कभी उनके उपभोग में कोई कमी आई उन्होंने सब कुछ सिर पर उठा लिया। पेट्रोल की कीमत अमेरिका में भी बढ़ रही है। महंगाई से वहां की जनता भी उतना ही त्रस्त है जितना दुनिया के अन्य हिस्सों में। अमेरिका में मध्यावधि चुनाव भी जल्दी ही होना है। ट्रंप सरकार को यह

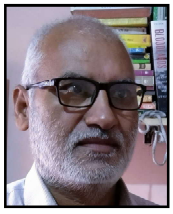

अमेरिका और चीन की बढ़ती निकटता भारत के लिए केवल बाहरी घटना नहीं बल्कि रणनीतिक मूल्यांकन का भी विषय है।

– अनिल तिवारी

डर है कि अगर समय रहते अमेरिकी जनता को अपेक्षित सुख सुविधाएं सहनीय स्थिति में नहीं उपलब्ध कराई गई तो इसका मतदान में उल्टा असर हो सकता है। अमेरिका आज दुनिया का सबसे बड़ा कर्जदार देश है। स्वदेशी जागरण मंच के सह–संयोजक डॉ. धनपत राम अग्रवाल ने अपने एक अध्ययन में लिखा है कि अमेरिका पर आज लगभग 40 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज है। ऐसे में अगर ट्रंप ईरान का मसला जल्द से जल्द नहीं सुलझाते हैं तो उनका कद राजनीतिक रूप से बौना हो जाने का डर है।

दूसरी तरफ चीन भी हतप्रभ और निरुपाय खड़ा है। अमेरिका ने जब वेनेजुएला पर कब्जा कर लिया तब चीन किनारे खड़ा होकर तमाशा देखता रहा। ईरान युद्ध के शुरू होने के बाद चीन का पत्ता लगभग खाड़ी देशों से भी साफ हो गया है। ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला बाधित होने के कारण महंगाई बढ़ी है और उत्पादन लागत 25 प्रतिशत से अधिक बढ़ गई है। चीन में युवा बेरोजगारी इस समय शीर्ष पर है। विदेशी पूंजी के पलायन से रियल एस्टेट क्षेत्र भी नकारात्मक हो गया है। चीन की स्थानीय सरकारों ने विकास की होड़ में अत्यधिक कर्ज लिया, लेकिन आज उसे पूंजी से कोई कमाई नहीं हो रही है। चीन के कई एक शहरों में सरकारी कर्मचारियों को लंबे समय से वेतन नहीं मिल पा रहा है।

खाड़ी युद्ध के कारण चीन और अमेरिका दोनों के कस–बल ढीले हो रहे हैं। दोनों की अकड़ सुरसा की तरह मुंह बाए खड़ी समस्या को देखकर न सिर्फ ढीली हुई है, बल्कि गलबहियां करने को भी प्रेरित किया है। यह मधुर मिलन दो ताकतवर देशों का नहीं बल्कि दो जख्मी दारोगाओं का एक दूसरे को सहलाने संभालने के लिए गिरकर समझौता करने का मौका भी है।

मालूम हो कि आज अमेरिका और

अमेरिका पर आज लगभग 40 ट्रिलियन डालर का कर्ज है। ऐसे में अगर ट्रंप ईरान का मसला जल्द से जल्द नहीं सुलझाते हैं तो उनका कद राजनीतिक रूप से बौना हो जाने का डर है।

चीन दोनों मिलकर वैश्विक अर्थव्यवस्था के लगभग 44 प्रतिशत हिस्से को प्रभावित करते हैं। विश्व व्यापार, तकनीकी विकास, उर्जा बाजार, वैश्विक निवेश, वित्तीय संस्थानों और अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक निर्णय पर इन दोनों देशों का प्रभाव है। विश्व अर्थव्यवस्था के संदर्भ में देखें तो अमेरिका और चीन के बीच तनाव कम होने से सबसे पहले वैश्विक बाजारों को राहत मिलेगी। इससे महंगाई पर भी नियंत्रण संभव हो सकेगा। लेकिन यह एक पक्ष है इसका दूसरा पक्ष यह है कि यदि दोनों महाशक्तियां वैश्विक व्यापारिक नियमों और आर्थिक नीतियों को अपने हितों के अनुसार तय करने लगे तो छोटे देशों की आर्थिक स्वतंत्रता प्रभावित हो सकती है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि विश्व धीरे–धीरे दो महाशक्तियों के प्रभाव वाले ढांचे की ओर बढ़ सकता है। अगर ऐसा होता है तो भारत जैसे देशों के लिए यह चिंता का विषय है, क्योंकि भारत हमेशा सामूहिक वैश्विक नेतृत्व का समर्थक रहा है।

एक अच्छी स्थिति यह है कि भारत न तो अमेरिका खेमे में है और न ही चीन के प्रभाव क्षेत्र में। भारत में रणनीतिक स्वायत्तता की नीति रही है। क्वॉड और ब्रिक्स जैसे मंच पर भारत की सक्रिय भूमिका है। भारत चीन का पड़ोसी देश है और दोनों देशों के बीच सीमा विवाद हैं, साथ ही व्यापारिक संबंध भी है। यही कारण है कि अमेरिका और चीन की बढ़ती निकटता भारत के लिए केवल बाहरी घटना नहीं बल्कि रणनीतिक मूल्यांकन का भी विषय है। भारत की शक्ति उसकी युवा आबादी, लोकतंत्र और डिजिटल क्षमता में निहित है, जबकि चीन विनिर्माण, निर्यात और पूंजी निवेश में आगे है। भारत ने 'चीन प्लस वन' की नीति को एक अवसर के रूप में देखा है। अनेक बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने चीन के विकल्प के रूप में भारत की ओर बढ़ाने का संकेत भी दिया है।

लेकिन दुनिया के दो दारोगाओं की इस हालिया मुलाकात के बाद आशंका व्यक्त की जा रही है कि अमेरिका और चीन मिलकर दुनिया को अपने–अपने प्रभाव क्षेत्र में बांटने का प्रयास कर सकते हैं। तो क्या दुनिया एक बार फिर घूम फिर कर उस बिंदु पर पहुंचने की ओर अग्रसर है जब विश्व राजनीति को महाशक्तियां अपनी उंगलियों पर नाचती थी? हालांकि प्रश्न का मुकम्मल उत्तर तो भविष्य के गर्भ में छिपा है लेकिन भारत जिस तरह से यूरोपीय संघ, अफ्रीकी देश, आसियान देशों के साथ मिलकर काम कर रहा है, इससे एक अच्छा संकेत मिलता है। भारत को बदलती राजनीतिक परिस्थितियों के लिहाज से अपने संकल्पों को मजबूत करना होगा तथा नए मानक गढ़ते हुए क्षमता को विस्तार देना होगा। क्योंकि सवाल यह नहीं कि अमेरिका और चीन क्या करेंगे? प्रश्न यह है कि भारत कैसे निपटेगा। इसका सीधा जवाब यही है कि "बिल्ली के भाग्य से सीकहर (दही दूध रखने का पात्र) टूटेगा" यानी 'चाईना प्लस वन' नीति के तहत भारत एक दिन वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा के ख्वाब जाल से बाहर निकाल कर भारत को विश्व हालात के मद्देनजर अपनी नीतियों को पुनर्समायोजित करना चाहिए। ❑❑

अटूट आस्था का शाश्वत प्रतीक सोमनाथ

भारत केवल एक भूभाग नहीं, अपितु हजारों वर्षों की सभ्यता, सांस्कृतिक चेतना और आध्यात्मिक परंपरा का जीवंत राष्ट्र है। भारतीय दर्शन कहता है कि आत्मा अजर–अमर है, वह केवल रूप बदलता है। इसी प्रकार भारत की सनातन संस्कृति और उसकी आस्था भी अनश्वर है। इतिहास साक्षी है कि इस चेतना को मिटाने के अनेक प्रयास हुए, किंतु न इसे झुकाया जा सका, न समाप्त किया जा सका। सौराष्ट्र में समुद्र तट पर अवस्थित श्री सोमनाथ मंदिर उसी अमर राष्ट्रीय चेतना और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का तेजस्वी प्रतीक है। विगत एक हजार वर्षों का कालखंड इसका प्रमाण है कि विदेशी आक्रांताओं की घृणा, कट्टरता और विध्वंस की नीति के आगे हमारी आस्था, साहस और सृजनशीलता हर क्षण अडिग रही। आज जब भारतवर्ष 20वीं शताब्दी में पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर के लोकार्पण की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है, तब यह केवल एक ऐतिहासिक घटना का स्मरण मात्र नहीं, अपितु भारत के आत्मा, उसकी आस्था और उसके स्वाभिमान को पुनः अनुभव करने का पावन अवसर भी है।

द्वादश ज्योतिर्लिंगों में प्रथम श्री सोमनाथ ने शताब्दियों के असंख्य आक्रमण और विध्वंस देखे, किंतु हर बार वह और अधिक गौरव एवं तेज के साथ पुनः स्थापित हुआ। महमूद गजनवी से लेकर औरंगजेब तक अनेक आक्रांताओं ने इसे मिटाने का प्रयास किया, पर वे स्वयं इतिहास में विलीन हो गए और सोमनाथ मंदिर अडिग खड़ा रहा है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जब देश विभाजन की पीड़ा, विस्थापन और अनिश्चितताओं से गुजर रहा था, तब हर भारतवासी यह अनुभव कर रहा था कि केवल राजनीतिक स्वतंत्रता पर्याप्त नहीं है, भारत को सांस्कृतिक स्वाधीनता का भी पुनर्स्थापन करना होगा। ऐसे समय में लौहपुरुष सरदार

'नया भारत' आज सनातन आस्था के सांस्कृतिक गौरव का उत्सव मना रहा है और गजनवी जैसे आततायियों के विध्वंस पर उल्लास, सृजन और वैभव का नव अंकुर प्रस्फुटित हो रहा है।
– योगी आदित्यनाथ

वल्लभभाई पटेल ने सोमनाथ के पुनर्निर्माण का संकल्प लिया। यह केवल एक मंदिर का पुनरुद्धार नहीं, स्वतंत्र भारत के सांस्कृतिक स्वाभिमान की पुनर्प्रतिष्ठा का संकल्प था। सरदार पटेल जानते थे कि यदि राष्ट्र को आत्मबल के साथ आगे बढ़ना है, तो उसे अपनी सांस्कृतिक चेतना और ऐतिहासिक गौरव से जुड़ना ही होगा। सोमनाथ का पुनर्निर्माण एक उद्घोष था कि स्वतंत्र भारत जड़ों से कटकर नहीं, बल्कि अपनी परंपराओं के साथ आगे बढ़ेगा। हालांकि सरदार पटेल अपने उस स्वप्न को साकार होते नहीं देखे सके, पर प्रथम राष्ट्रपति डा. राजेंद्र प्रसाद तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की अनिच्छा के बावजूद सोमनाथ मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल हुए थे। डा. राजेंद्र प्रसाद का यह निर्णय इसकी उद्घोषणा था कि भारत के सांस्कृतिक आत्मा को किसी वैचारिक आग्रह से दबाया नहीं जा सकता।

आज, अमृतकाल के कालखंड में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत 'स्व' से साक्षात्कार कर रहा है। यह सांस्कृतिक पुनर्जागरण का ही कालखंड है। जो कार्य स्वतंत्र भारत में सरदार पटेल और डा. राजेंद्र प्रसाद जी ने प्रारंभ किया था, वही चेतना आज मोदी जी के नेतृत्व में नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ती दिखाई देती है। अयोध्या में श्रीरामजन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण भी पांच शताब्दियों के संघर्ष, धैर्य और सांस्कृतिक स्वाभिमान की ऐतिहासिक परिणति है। कभी जिन आक्रांताओं ने श्रीरामजन्मभूमि को अपमानित कर भारत की आस्था पर प्रहार किया था, आज उनका नाम इतिहास के अंधकार में खो चुका है। प्रभु श्रीराम का भव्य मंदिर पूरे वैभव के साथ खड़ा है।

इस क्रम में श्रीकाशी विश्वनाथ धाम का पुनर्विकास काशी की जीवंतता और भारत की सनातन चेतना के पुनरुत्थान का प्रतीक है। आज वैश्विक स्तर पर भी भारत की इस सांस्कृतिक चेतना को नई स्वीकृति प्राप्त हो रही है। योग, आयुर्वेद, भारतीय दर्शन, अध्यात्म और सनातन जीवनदृष्टि के प्रति विश्व का आकर्षण निरंतर बढ़ रहा है। यह केवल सांस्कृतिक प्रभाव नहीं है, यह भारत की उस शाश्वत दृष्टि की स्वीकृति है, जो मानवता को संतुलन, सहअस्तित्व और समरसता का मार्ग दिखाती है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 'नया भारत' आज 'सोमनाथ स्वाभिमान पर्व' के रूप में सनातन आस्था के सांस्कृतिक गौरव का उत्सव मना रहा है और गजनी जैसे आततायियों के विध्वंस पर उल्लास, सृजन और वैभव का नव– अंकुर प्रस्फुटित हो रहा है।

सोमनाथ का पुनर्निर्माण एक उद्घोष था कि स्वतंत्र भारत जड़ों से कटकर नहीं, बल्कि अपनी परंपराओं के साथ आगे बढ़ेगा। हालांकि सरदार पटेल अपने उस स्वप्न को साकार होते नहीं देखे सके, पर प्रथम राष्ट्रपति डा. राजेंद्र प्रसाद तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की अनिच्छा के बावजूद सोमनाथ मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल हुए थे।

सोमनाथ का पुनर्निर्माण इसी व्यापक सांस्कृतिक विमर्श का महत्वपूर्ण आधार है। यह हमें स्मरण कराता है कि कोई भी राष्ट्र केवल आर्थिक शक्ति से महान नहीं बनता। उसकी वास्तविक शक्ति उसकी सांस्कृतिक चेतना, उसके ऐतिहासिक आत्मविश्वास और उसकी सभ्यतागत निरंतरता में निहित होती है। जिन राष्ट्रों ने अपनी जड़ों को भुला दिया, वे इतिहास में धीरे–धीरे कमजोर पड़ गए, किंतु भारत ने हर युग में अपने आत्मा को सुरक्षित रखा। आज जब हम पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर के लोकार्पण की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, तब यह अवसर नई पीढ़ी को भारत के वास्तविक स्वरूप से परिचित कराने का भी है। यह पीढ़ी भारत की सांस्कृतिक विरासत की उत्तराधिकारी भी है। उसे यह समझना होगा कि भारत का उत्थान केवल आर्थिक प्रगति से संभव नहीं है। भारत तब पूर्ण रूप से विकसित और शक्तिशाली बनेगा, जब वह अपने आत्मा से जुड़कर आगे बढ़ेगा। श्री सोमनाथ मंदिर हमें यह भी स्मरण कराता है कि पुनर्निर्माण केवल भौतिक नहीं होता, वह मानसिक और राष्ट्रीय भी होता है। जब कोई समाज अपने टूटे हुए प्रतीकों को पुनः स्थापित करता है, तब वह केवल भवन नहीं बनाता, बल्कि अपने आत्मविश्वास को पुनर्जीवित करता है। पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर की 75वीं वर्षगांठ हमें यही प्रेरणा देती है कि राष्ट्र का स्वाभिमान उसकी सांस्कृतिक चेतना से जुड़ा होता है। यदि संस्कृति सुरक्षित है, तो राष्ट्र का भविष्य भी सुरक्षित है।

आईये, इस अवसर पर हम सब यह संकल्प लें कि भारत की महान सांस्कृतिक परंपरा, आध्यात्मिक विरासत और राष्ट्रीय मूल्यों को और अधिक सशक्त बनाएंगे। भावी पीढ़ियों को अपनी सभ्यता का गौरव समझाएंगे और अमृतकाल में भारत को उसके वास्तविक वैश्विक स्वरूप तक पहुंचाने में अपनी सक्रिय भूमिका निभाएंगे।

जय सोमनाथ! ❑❑

(लेखक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं)।

देश वापसी की अपील के मायने

हाल ही में प्रौद्योगिकी, खासतौर पर आईटी और आर्टिफिशल इंटेलिजेंस में आत्मनिर्भरता के प्रबल समर्थक एवं वैश्विक स्तर पर जानीमानी सॉफ्टवेयर कंपनी 'जोहो' के प्रोमोटर एवं पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकारी श्रीधर वेंबू ने अमरीका में रह रहे भारतीयों को एक खुला पत्र लिखकर देश वापिस आकर भारत के भविष्य निर्माण हेतु सहायता की अपील कर देश और दुनिया में एक नई बहस छेड़ दी है। उनकी इस अपील में मुख्य बात यह है कि भारत का विश्व में सम्मान भारत के प्रौद्योगिक विकास पर निर्भर करता है। पिछले लम्बे समय से भारत ने दुनिया को अपनी प्रतिभा का निर्यात किया है, जिसे 'ब्रेनड्रेन' कहा जाता है। उस समय भारत की वैश्विक स्तर की प्रौद्योगिकी के निर्माण में पिछड़ गया। लेकिन आज भारत के पास क्षमता है कि वो विश्वस्तरीय प्रौद्योगिकी के विकास पर आगे बढ़ सके। लेकिन उसे जल्द कर सकने के पहली शर्त यह है कि शेष दुनिया में बसे भारतीय जो अवसरों के अभाव में देश छोड़ गए थे, वापस आएँ।

इससे पहले भी कई बार भारतीयों को वापिस आने की अपील कई प्रमुख व्यक्ति समय–समय पर करते रहे हैं, लेकिन उस पर इतनी बहस कभी नहीं छिड़ी, जितनी श्रीधर वेंबू के आह्वाहन के बाद छिड़ी है। उसका कारण यह है कि अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारतीय मूल के लोगों को लेकर कई प्रकार के अशोभनीय वक्तव्य दे रहे हैं। पिछले काफी समय से वो लगातार कह रहे हैं कि विदेशियों के कारण अमरीकियों के लिए रोजगार के अवसर घट रहे हैं। उन्होंने बार–बार यह कहा है कि एच–1बी वीजा के प्रावधान का इस्तेमाल करते हुए कंपनियां विदेशों से सस्ते श्रमिक लेकर आती हैं, जो अमरीकी कार्मिकों को रोजगार से बाहर कर देते हैं। इसलिए उन्होंने एच–1 बी वीजा के नियमों को कड़ा कर दिया है और विदेशी कार्मिकों की सख्ती से जांच–पड़ताल भी शुरू कर दी है। गौरतलब है कि एच–1 बी वीजा के माध्यम से अधिकांश भारतीय अमरीका में सॉफ्टवेयर और अन्य प्रकार की प्रौद्योगिकी में कार्यरत हैं, इसके द्वारा अमरीकी और भारतीय कंपनियां भारतीयों को रोजगार प्रदान करती हैं।

दिलचस्प बात यह है कि पूर्व में राष्ट्रपति ट्रंप भारतीयों लोगों और भारतीय नेतृत्व के प्रशंसक भी रहे हैं। पूर्व में वो यह कहते रहें कि भारत एक महान मित्र और रणनीतिक साझेदार है। हाउडी–मोदी जैसे कार्यक्रमों में उन्होंने भारतीय अमरीकी लोगों की भूरी–भूरी प्रशंसा भी की और कहा कि भारतीय अमरीकी अतुलनीय हैं और वे अमरीकी अर्थव्यवस्था में भारी योगदान भी दे रहे हैं। लेकिन हाल ही में उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, 'ट्रूथ सोशल' पर भारतीय लोगों और भारत के बारे में अपशब्द भी कहे हैं, जिसे भारत के विदेश मंत्रालय द्वारा अज्ञानपूर्ण, अनुचित और भद्दे स्वाद का बताया गया है। राष्ट्रपति ट्रंप का यह बयान अमरीका में अमरीकी नागरिकता के जन्मसिद्ध अधिकार बारे में उनके वक्तव्य का एक हिस्सा था। हालांकि अमरीकी प्रशासन ने इस बयान के बाद कहा कि ट्रंप भारत को एक महान देश मानता है और इसके नेतृत्व को अपना अच्छा मित्र समझता है। इससे पहले राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत समेत अपने लगभग सभी व्यापार साझेदारों पर भारी टैरिफ लगाकार सभी देशों को नाराज करने का काम भी किया है, हालांकि अमरीकी सर्वोच्च न्यायालय ने उनमें से अधिकांश टैरिफ को रद्द करने का निर्णय भी दिया है।

इससे पहले भी कई बार भारतीयों को वापिस आने की अपील कई प्रमुख व्यक्ति समय–समय पर करते रहे हैं, लेकिन उस पर इतनी बहस कभी नहीं छिड़ी, जितनी श्रीधर वेंबू के आह्वाहन के बाद छिड़ी है।

– स्वदेशी संवाद

श्रीधर वेंबू की भारतीयों को वापिस आकर अपने देश के प्रौद्योगिकी विकास में मद्द करने की अपील आज के संदर्भ में दो कारणों से अधिक मायने रखती है, पहला, बदलते भू–राजनीतिक परिवेश में अमरीकी प्रशासन, विशेषतौर पर राष्ट्रपति ट्रंप के बयान और कार्यवाही, जिससे अमरीका में भारतीयों के भविष्य पर प्रश्नचिन्ह लग रहा है। और दूसरा, भारत प्रौद्योगिकी की दृष्टि से प्रगति करने के लिए केवल तत्पर ही नहीं है, बल्कि उसकी संभावनाएं भी बढ़ती जा रही हैं। एक समय था जब भारत प्रौद्योगिकी दृष्टि से काफी पीछे था, और हमारे श्रेष्ठ शिक्षा संस्थानों जैसे आईआईटी, मेडिकल और इंजनियरिंग कॉलेजों के ग्रेजुएट, प्रबंधन विशेषज्ञ, वैज्ञानिक और पेशेवर भारत में प्रतिकूल परिस्थितियों के चलते अपनी प्रतिभा के अनुरूप रोजगार नहीं पा सकते थे। ऐसे में हमारे श्रेष्ठ युवाओं ने विदेशों की ओर रूख कर लिया। इन युवाओं ने उन देशों के निर्माण और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन भी किया। गौरतलब है कि अमरीका में सिर्फ 1.5 प्रतिशत भारतीय मूल के लोग हैं, जिनमें से दो तिहाई अप्रवासी हैं और एक तिहाई का जन्म वहां हुआ है। लेकिन खास बात यह है कि अपनी मेहनत, शिक्षा और सामर्थ्य के कारण वे औसत अमरीकी लोगों से कई गुणा ज्यादा कमाते हैं और अमरीका के राजस्व में उनका हिस्सा 6 प्रतिशत है। अमरीकी सरकार को भारतीय मूल के लोगों से 300 अरब डालर राजस्व की प्राप्ति होती है। भारतीय मूल के लोग विभिन्न समूहों की तुलना में उच्चतम आय प्राप्त करने वाला वर्ग है। भारतीयों की अमरीका के सबसे ज्यादा आमदनी वाले प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य और वित्त जैसे क्षेत्रों में मजबूत उपस्थिति है। उनकी शिक्षा और पेशेवर कुशलता बहुत अधिक है और यही नहीं उद्यमशीलता और व्यवसायों के स्वामित्व के नाते भी उनकी

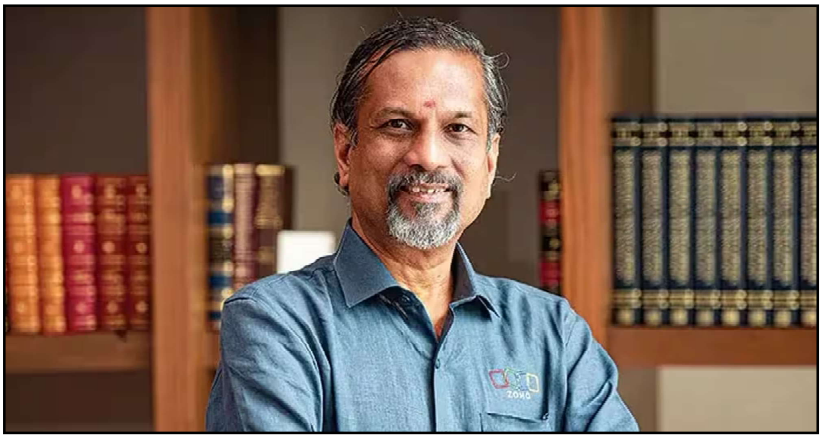

विशेष भूमिका है। कई बड़ी कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी भारतीय मूल के हैं। जितना पैसा भारतीय मूल के लोग टैक्सों में देते हैं, उससे कहीं कम वो सामाजिक सुरक्षा और अन्य प्रकार के सरकारी लाभ लेते हैं।

लेकिन भारत में कुछ लोगों ने इस अपील को बहुत सकारात्मक रूप से नहीं लिया है, और वे श्रीधर वेंबू की आलोचना कर रहे हैं। लेकिन साथ ही कई लोग उनका समर्थन भी कर रहे हैं। यह ज़ाहिर है कि भारतीय मूल के जो लोग वहाँ एक या उससे ज्यादा पीढ़ियों से रह रहे हैं, उनके लिए अपना सामान समेटकर भारत वापस लौटना आसान नहीं है, भले ही वे भारत से प्यार करते हों और भारत की विकास गाथा में विश्वास रखते हों। ऐसे बहुत से लोग हैं जो मानते हैं कि पर्यावरण, बुनियादी ढाँचा, जीवन स्तर, नौकरी और व्यवसाय के अवसर भारत की तुलना में अमेरिका में कहीं बेहतर हैं। कुछ लोग तो जान–बूझकर अपने बच्चों की शिक्षा के उद्देश्य से अमेरिका चले गए हैं। इसलिए, श्रीधर वेंबू की अपील का अमेरिका में ही रुके रहने के उनके फ़ैसले पर बहुत ही सीमित असर पड़ सकता है।

लेकिन, ऐसे भी बहुत से लोग हैं जिन्होंने बेहतर शिक्षा और उसके बाद एक अच्छी नौकरी के लिए भारत छोड़ा था; लेकिन अब उन्हें अमेरिकी प्रशासन से बुरा बर्ताव मिल रहा है, खासकर वीज़ा से जुड़ी अनिश्चितता, मनाही तथा अन्य पाबंदियों के मामले में। ऐसे बहुत से लोग हैं जो भारत में अवसर देखते हैं, वहाँ के फलते–फूलते स्टार्ट–अप और व्यावसायिक अवसरों के कारण, और भारत की नवाचार, तकनीकी विकास और तेज़ी से बेहतर होते बुनियादी ढाँचे की दिशा में हो रही प्रगति के कारण। ऐसे भी बहुत से लोग हैं जिनके मन में अपनी मातृभूमि के प्रति देशभक्ति की भावना है और उन्होंने इस बारे में सोचना शुरू कर दिया है, और वे वास्तव में भारत वापस लौट भी रहे हैं। ऐसे भी बहुत से लोग हैं जो भारत के साथ अपने मज़बूत रिश्ते बनाए हुए हैं, वे तकनीक के विकास में मदद कर रहे हैं, व्यवसायों और स्टार्ट–अप में निवेश कर रहे हैं, और भारत के साथ अपने करीबी संबंध बनाए हुए हैं।

ऐसा लगता है कि यह सब रातों–रात तो नहीं होगा, लेकिन देर–सवेर, भारतीय मूल के लोग, जिनमें ग्रीन कार्ड और अमेरिकी पासपोर्ट धारक, तथा भारतीय पासपोर्ट वाले एनआरई भी शामिल हैं, भारत की ओर आकर्षित हो सकते हैं; इसके पीछे देशभक्ति की भावना, बेहतर विकास के अवसर, अच्छा बुनियादी ढाँचा, जीवन की सुगमता आदि कारण हो सकते हैं। लेकिन, हमें यह समझना होगा कि यह समय 'ब्रेन ड्रेन' (प्रतिभा पलायन) के बजाय 'ब्रेन गेन' (प्रतिभा लाभ) के लिए एक बहुत ही उपयुक्त अवसर है। ❑❑

(डॉ. अश्वनी महाजन की वाल से)

ज्ञान के मंदिर पर बाजार का कब्ज़ा

आज का विद्यालय केवल ज्ञान का मंदिर नहीं रह गया है; उसकी चौखट पर बाजार खड़ा दिखाई देता है। सजधज कर, आकर्षक पैकेजिंग और अपने विस्तार की असीम संभावनाओं के साथ। कभी शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति के सर्वांगीण विकास, नैतिकता और समाज निर्माण से जुड़ा था, परंतु अब धीरे–धीरे यह एक 'सेवा' से 'उत्पाद' में बदलती जा रही है। इस परिवर्तन ने शिक्षा के मूल स्वरूप को चुनौती दी है, और यह प्रश्न उठाया है कि क्या हम वास्तव में सीख रहे हैं, या केवल खरीद रहे हैं?

विद्यालयों के बाहर कोचिंग संस्थानों, गाइड पुस्तकों, डिजिटल ऐप्स और निजी ट्यूशन का जाल फैल चुका है। यह पूरा तंत्र बच्चों और अभिभावकों को यह विश्वास दिलाता है कि बिना इन 'अतिरिक्त साधनों' के सफलता संभव नहीं। परिणामस्वरूप, स्कूल में होने वाली पढ़ाई का महत्व घटने लगता है। छात्र कक्षा में उपस्थित तो रहते हैं, पर उनका ध्यान अक्सर उस 'बाजार' की ओर होता है जो उन्हें तेज़, आसान और सुनिश्चित सफलता का वादा करता है।

बाजार की यह घुसपैठ केवल शैक्षणिक सामग्री तक सीमित नहीं है। आज स्कूलों में ब्रांडेड यूनिफॉर्म, महंगे बैग, विशेष किताबें, और अनिवार्य गतिविधियों के नाम पर अतिरिक्त शुल्क, ये सब मिलकर शिक्षा को महंगा और असमान बना रहे हैं। शिक्षा का अधिकार तो सबको है, लेकिन गुणवत्तापूर्ण शिक्षा अब धीरे–धीरे केवल उन लोगों तक सीमित होती जा रही है जो इसे 'अफोर्ड' कर सकते हैं। इससे समाज में एक नया वर्ग विभाजन उत्पन्न हो रहा है–शिक्षा आधारित असमानता।

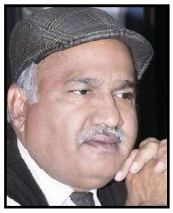

यह निर्णय हमें लेना है कि हम अपने स्कूलों को बाजार का विस्तार बनने देंगे या ज्ञान का केंद्र बनाए रखेंगे। यदि शिक्षा भीतर से सिमटती रही और बाजार बाहर से बढ़ता गया, तो हम एक ऐसे समाज की ओर बढ़ेंगे जहाँ डिग्रियाँ तो होंगी, पर ज्ञान का अभाव होगा।

– डॉ. विजय गर्ग

डिजिटल क्रांति ने भी इस बाजार को और मजबूत किया है। ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म, एड–टेक कंपनियाँ और वर्चुअल क्लासेस ने शिक्षा को तकनीकी रूप से उन्नत तो बनाया है, लेकिन इसके साथ ही शिक्षा का व्यावसायीकरण भी बढ़ा है। विज्ञापन यह बताते हैं कि 'स्मार्ट लर्निंग' ही सफलता की कुंजी है, जबकि वास्तविकता यह है कि तकनीक केवल एक माध्यम है, लक्ष्य नहीं।

इस परिदृश्य में सबसे अधिक प्रभावित होता है–शिक्षक और छात्र का संबंध। शिक्षक, जो कभी मार्गदर्शक और प्रेरणास्रोत हुआ करता था, अब कई बार केवल एक 'सेवा प्रदाता' के रूप में देखा जाने लगता है। वहीं छात्र, जिसे जिज्ञासु और खोजी होना चाहिए, वह अंकों और रैंकिंग के दबाव में अपनी मौलिकता खोने लगता है। शिक्षा का मानवीय पहलू धीरे–धीरे सिमटता जा रहा है।

यह भी सच है कि बाजार पूरी तरह नकारात्मक नहीं है। उसने शिक्षा में प्रतिस्पर्धा, नवाचार और संसाधनों की उपलब्धता को बढ़ाया है। लेकिन जब बाजार का उद्देश्य केवल लाभ कमाना हो जाए, और शिक्षा का उद्देश्य पीछे छूट जाए, तब समस्या उत्पन्न होती है। संतुलन का अभाव ही सबसे बड़ी चुनौती है।

आवश्यकता इस बात की है कि हम शिक्षा को फिर से उसके मूल उद्देश्य से जोड़ें। स्कूलों को केवल परीक्षा परिणामों का केंद्र न बनाकर, उन्हें विचार, संवाद और सृजन का मंच बनाना होगा। सरकार, शिक्षण संस्थानों और समाज को मिलकर यह सुनिश्चित करना होगा कि शिक्षा सुलभ, समावेशी और मूल्य आधारित बनी रहे।

अभिभावकों को भी इस भ्रम से बाहर निकलना होगा कि अधिक खर्च का अर्थ बेहतर शिक्षा है। बच्चों को यह समझाना होगा कि सीखना एक प्रक्रिया है, न कि कोई उत्पाद जिसे खरीदा जा सके। शिक्षकों को भी अपने भूमिका को पुनः परिभाषित करना होगा, वे केवल पाठ पढ़ाने वाले नहीं, बल्कि जीवन के मार्गदर्शक हैं।

शिक्षा का व्यवसायीकरणः एक कड़वी सच्चाई

आधुनिक स्कूलों में अब केवल पढ़ाई नहीं बिकती, बल्कि सुविधाओं का एक पूरा ''पैकेज'' बिकता है। स्कूल अब एक शैक्षणिक संस्थान कम और एक कॉर्पोरेट ऑफिस ज्यादा नजर आते हैं।

''एडमिशन का खेलः'' भारी–भरकम 'डोनेशन' और 'डेवलपमेंट फीस' के नाम पर अभिभावकों की जेबों पर डाका डाला जा रहा है।

''यूनिफॉर्म और किताबों का एकाधिकारः'' अधिकांश स्कूलों ने अब अपनी चौखट के भीतर ही दुकानें खोल ली हैं। जूते, मोजे, टाई से लेकर कॉपियों तक, सब कुछ स्कूल द्वारा निर्धारित दुकान से ही लेना अनिवार्य है, जो बाजार भाव से कहीं अधिक महंगी होती हैं।

''ईवेंट्स और दिखावाः'' 'एनुअल फंक्शन' और 'स्पोर्ट्स डे' अब प्रतिभा निखारने के बजाय स्कूल की भव्यता दिखाने के विज्ञापन बन गए हैं।

सिमटती शिक्षा

जैसे–जैसे बाजार का प्रभाव बढ़ा है, शिक्षा का मूल स्वरूप संकुचित होता गया है।

1. ''ज्ञान बनाम ग्रेड्सः'' आज की शिक्षा का पैमाना 'बच्चे ने क्या सीखा' से बदलकर 'बच्चे ने कितने प्रतिशत अंक पाए' पर टिक गया है। शिक्षा अब चहुंमुखी विकास के बजाय एक ''रैंक–बनाने वाली मशीन'' बनकर रह गई है।

2. ''शिक्षकों की स्थितिः'' एक शिक्षक, जिसका कार्य अध्यापन था, अब वह मार्केटिंग, डेटा एंट्री और फीस कलेक्शन जैसे गैर–शैक्षणिक कार्यों में उलझा दिया गया है। जब शिक्षक ही बोझ तले दबा होगा, तो शिक्षा की गुणवत्ता का गिरना स्वाभाविक है।

3. ''कोचिंग कल्चर का उदयः'' विडंबना देखिए कि स्कूल की भारी फीस भरने के बाद भी बच्चा 'कोचिंग' जाने को मजबूर है। यह इस बात का प्रमाण है कि स्कूल के भीतर की शिक्षा छात्र की जरूरतों को पूरा करने में अक्षम साबित हो रही है।

समाज पर प्रभाव

यह 'बाजारीकरण' समाज में एक गहरी खाई पैदा कर रहा है। शिक्षा अब अधिकार नहीं, बल्कि एक ''विलासिता'' बनती जा रही है।

"जब शिक्षा एक उत्पाद बन जाती है, तो छात्र एक ग्राहक बन जाता है। और ग्राहक को संतुष्ट करना तो आसान है, लेकिन एक नागरिक को शिक्षित करना कठिन।"

पैसे के दम पर खरीदी गई डिग्रियां डिब्बों में बंद कागज के टुकड़ों जैसी हैं। इनसे कौशल और नैतिकता गायब हैं। यदि शिक्षा का उद्देश्य केवल पैसा कमाना रह गया, तो हम एक ऐसी पीढ़ी तैयार कर रहे हैं जो आर्थिक रूप से समृद्ध तो हो सकती है, लेकिन मानसिक और चारित्रिक रूप से दरिद्र होगी।

अंततः, समय आ गया है कि हम रुककर सोचें। क्या हम अपने बच्चों को केवल एक 'उपभोक्ता' बनाना चाहते हैं या एक सजग इंसान? सरकार, समाज और अभिभावकों को मिलकर इस बाजारीकरण के खिलाफ आवाज उठानी होगी। स्कूल की चौखट से बाजार को बाहर धकेलना जरूरी है ताकि भीतर की शिक्षा को फिर से फैलने और पनपने का अवसर मिल सके। शिक्षा का उद्देश्य श्करियरश बनाना जरूर हो, लेकिन इसका आधार 'चरित्र' होना चाहिए।

यह निर्णय हमें लेना है कि हम अपने स्कूलों को बाजार का विस्तार बनने देंगे या ज्ञान का केंद्र बनाए रखेंगे। यदि शिक्षा भीतर से सिमटती रही और बाजार बाहर से बढ़ता गया, तो हम एक ऐसे समाज की ओर बढ़ेंगे जहाँ डिग्रियाँ तो होंगी, पर ज्ञान का अभाव होगा।

समय की मांग है कि हम इस प्रवृत्ति को पहचानें और शिक्षा को उसके असली स्वरूप–मानव विकास और सामाजिक उत्थान–की ओर वापस ले जाएँ। ❑❑

(डॉ विजय गर्ग सेवानिवृत्त प्रिंसिपल मलोट पंजाब)

खतरनाक है गर्मी की आपदा

प्रसिद्ध प्रकृतिवादी इतिहासकार डेविड एटनबरो ने कुछ समय पहले एक सेमिनार के दौरान अपने हालिया शोध के आधार पर चेतावनी दी थी, "भीषण गर्मी केवल असुविधा नहीं है, यह मानव अस्तित्व के लिए खतरा बनती जा रही है।"

देश का एक बड़ा हिस्सा इस समय आग की भट्ठी बना हुआ है। उत्तर से लेकर मध्य भारत तक ज्यादातर शहरों में औसत तापमान इस वर्ष सामान्य से 3–5 डिग्री सेल्सियस ऊपर चल रहा है। मौसम विज्ञानियों की राय है कि अल नीनो की वजह से गर्मी अभी और अधिक परेशान कर सकती है।

तपती और चिलचिलाती गर्मी के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बढ़ती गर्मी से निजात पाने के लिए राष्ट्रव्यापी दृष्टिकोण अपनाने पर जोर दिया है। दिल्ली में आयोजित कैबिनेट मीटिंग के दौरान उन्होंने सभी मंत्रालयों से कहा है कि हीट वेव से लोगों की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाए जाएं। प्रधानमंत्री ने केंद्र और राज्य सरकारों तथा नागरिकों के सामूहिक प्रयास की बात को गंभीरता से रेखांकित किया है। उन्होंने इस बाबत जरूरत के अनुसार कार्य योजना तैयार करने के लिए संबंधित मंत्रालयों को निर्देश भी दिया है। प्रधानमंत्री ने बैठक के दौरान कहा है कि हीट वेव का मामला केवल मौसम का मामला नहीं रह गया है इससे बचाव के लिए हमें दीर्घकालिक योजना तैयार करनी चाहिए।

विभिन्न अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट्स के अनुसार इस बार 27 अप्रैल, 19 मई, 26 तथा 27 मई चार ऐसे दिन गुज़रे जब धरती के सबसे ज्यादा गर्म 50 शहरों में सभी नाम भारत के शहरों के थे। विश्व स्वास्थ्य संगठन की हालिया रिपोर्ट भी यही चेतावनी दे रही है कि देश के 50 प्रतिशत से ज्यादा शहरों में भीषण गर्मी का खतरा 'अधिक' से आगे बढ़कर 'बेहद अधिक' के स्तर तक पहुंच चुका है। लू वाले दिनों में भी बेहद बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वर्ष 2015 से 2020 के दौरान लू वाले दिनों का औसत 7.4 और वर्ष 2020 से 2022 के 9.5 दिन से बढ़कर 32.2 दिन तक का हो गया है और इसकी मियाद लगातार बढ़ती ही जा रही है।

भारत में गर्मी अब हर साल एक नया रिकॉर्ड बना रही है। चिंता की बात यह है कि

जलवायु परिवर्तन के कारण गर्मी बढ़ी है। गर्मी के बढ़ने से लोगों की परेशानियों भी बढ़ी है। आगे के दिन और अधिक कठिन होने के संकेत हैं।

– डॉ. दिनेश प्रसाद मिश्र

भारत इस समय दुनिया की सबसे ज्यादा गर्म जगह में से एक बनकर सामने आया है। देश की 76 प्रतिशत आबादी सामान्य से अधिक गर्मी के बीच जीवन जीने के लिए मजबूर है।

दिन तो तपते ही हैं अब रातें भी राहत देने वाली नहीं रही। मई की 20 तारीख को दिल्ली ने 13 साल की सबसे गर्म रात देखी जबकि 25 मई की रात को यह रिकॉर्ड भी टूट गया और उस रात 14 साल में सर्वाधिक गर्मी विभाग द्वारा दर्ज की गई। 25 मई को न्यूनतम तापमान सामान्य से 5.4 डिग्री सेल्सियस ऊपर रहा। कूलर, एसी जैसे उपकरण रात को ठंडा करने में नाकाम रहे। रातें पूरी तरह से हीटर बनी रही। देश की राजधानी दिल्ली के कई स्थानों पर रात का न्यूनतम तापमान 32.5 डिग्री तक दर्ज हुआ। इन दिनों भीषण गर्मी और लू के चलते बेहाल लोगों द्वारा बिजली की मांग भी पारे की तरह बढी है।

भारत इस समय दुनिया की सबसे ज्यादा गर्म जगह में से एक बनकर सामने आया है। देश की 76 प्रतिशत आबादी सामान्य से अधिक गर्मी के बीच जीवन जीने के लिए मजबूर है। साल दर साल गर्मी बढ़ने की वजह से सार्वजनिक स्वास्थ्य पर संकट गहराता जा रहा है। हीट वेव की तीव्रता तथा समय सीमा बढ़ने के कारण लोग हलकान हैं। शहरों पर संकट अधिक है। शहरों में कंक्रीट के घर बढ़ रहे हैं जबकि हरियाली लगातार कम हो रही है। कंकरीट स्ट्रक्चर्स और प्रदूषण की वजह से अधिकांश शहरी "अर्बन हीट आईलैंड इफेक्ट" झेल रहे हैं।

मौसम की यह मार दो तरफा है। आम लोगों के स्वास्थ्य पर तो गंभीर प्रतिकूल असर पड़ ही रहा है अत्यधिक गर्मी के कारण अर्थव्यवस्था की रफ्तार भी सुस्त पड़ जाती है। नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के मुताबिक 2025 में हीट स्ट्रोक के सात हजार से ज्यादा संदिग्ध मामले सामने आए थे। हालांकि हमारे देश में हीट स्ट्रोक और उससे होने वाली मौतों का सही आंकड़ा कभी रिपोर्ट नहीं हो पाता है। यह एक मोटे अनुमान के आधार पर जारी किया जाता रहा है। जबकि वास्तविक आंकड़ा बहुत बड़ा होता है। देश की एक बड़ी आबादी मौसम का सीधा वार झेलती है। गिग वर्कर्स, दिहाड़ी मजदूर, स्ट्रीट वेंडर्स के रूप में असंख्य कामगार धूप की परवाह किए बगैर बाहर निकलते हैं। यह वह लोग हैं जो अगर घर पर बैठ जाएं तो उनका काम नहीं चल सकता। उनके बैठने से देश के काम की रफ्तार भी धीमी हो पड़ जाएगी। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक 65 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों में गर्मी से होने वाली मौतों की संख्या में लगभग 85 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

गर्मी के कारण कार्य क्षमता पर भी सीधा असर पड़ता है। काम के घंटे तो कम होते ही हैं उत्पादकता भी कम हो जाती है जो कि अर्थव्यवस्था के लिए नुकसानदायक है। मैकेंजी ग्लोबल इंस्टिट्यूट के आकलन के मुताबिक वर्ष 2030 तक गर्मी की वजह से सकल घरेलू उत्पाद पर भी बड़ा नकारात्मक प्रभाव दिख सकता है।

गर्मी का यह प्रचंड रूप तथा गर्मी को लेकर विभिन्न राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों की रिपोर्ट एक गंभीर चेतावनी तथा बड़ी आपदा का संकेत दे रहे हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम के और अधिक बिगड़ने की आशंका है।

प्रधानमंत्री ने बढ़ती गर्मी की समस्या को गंभीरता से लिया है तथा विभिन्न मंत्रालयों को इसके लिए कमर कसने का निर्देश भी दिया है। प्रधानमंत्री की यह अपील कि 'गर्मी भी एक आपदा है', और इसके निवारण के लिए आवश्यक एहतियाती कदम हर हाल में उठाए ही जाने चाहिए, अति प्रासंगिक भी है और जरूरी भी है। गर्मी को ज्यादा गंभीरता से लेने और सावधानी बरतने की सलाह देते हुए उन्होंने गर्मी से होने वाली परेशानियों को नजरअंदाज न करने और दूसरों का भी ख्याल रखने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा है कि दरअसल हीट वेव को राष्ट्रीय आपदा की तरह देखा जाना चाहिए और जिस तरह बाढ़, भूस्खलन या इस तरह के दूसरे संकट के समय लोग एकजुट हो जाते हैं इस तरह गर्मी को लेकर भी जागरूकता बढ़ाने और संवेदनशील कदम उठाने की जरूरत है।

जलवायु परिवर्तन के कारण गर्मी बढ़ी है। गर्मी के बढ़ने से लोगों की परेशानियों भी बढ़ी है। आगे के दिन और अधिक कठिन होने के संकेत हैं। हालात इस कदर बिगड़ जाए कि संभालने में कठिनाई हो इसके पहले ही सरकारें सामूहिक कार्य योजना बनाकर आगे आए तो बहुत हद तक आम लोगों को राहत दी जा सकती है। स्थानीय स्तर पर जिस तरह सर्दियों या बारिश के लिए तैयारी की जाती है उसी तरह अब देश भर में गर्मियों के लिए भी जरूरत के अनुसार पूर्व तैयारी करनी चाहिए। इसके साथ ही साथ शहरों में स्वच्छ ऊर्जा में निवेश और ऊर्जा उत्पादन की वृद्धि को प्राथमिकता देना होगा ताकि कठिन से कठिन समय में ऊर्जा की आपूर्ति होती रहे। शहरों में अगर पर्याप्त बिजली मिलती रहेगी तो लोग हीट वेव से बचने के लिए कोई ना कोई इंतजाम कर ही लेंगे। ❑❑

'आयुष्मान-भारत' से कम हो रहा है इलाज का बोझ

सरकार की कल्याणकारी योजना आयुष्मान भारत लोगों के लिए राहत का सबक बनी है। इलाज पर होने वाले खर्च में निजी खर्च की भागीदारी धीरे-धीरे घट रही है। केंद्र की सरकार 'सबका साथ, सबका विकास, सबमें विश्वास और सबका स्वास्थ्य' के नारे को धरातल पर उतरने में धीरे-धीरे कामयाबी हासिल कर रही है।

– गणेश गौतम

भारत में तकरीबन सभी नागरिकों तक अच्छे इलाज की पहुंच सुनिश्चित होने के साथ-साथ इलाज पर लोगों की जेब से होने वाले खर्चे में भी अप्रत्याशित रूप से कमी आई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक कल स्वास्थ्य खर्च में नागरिकों की जेब खर्च की हिस्सेदारी घटकर अब मात्र 43.4 प्रतिशत रह गई है। वर्ष 2013-14 में यह आंकड़ा 64.2 प्रतिशत था, यानी करीब एक दशक में इसमें 21 प्रतिशत की कमी आई है।

चूंकि भारत एक कल्याणकारी राज्य है इसलिए रोजी-रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई और दवाई राज्यों और केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। वर्तमान सरकार ने स्वास्थ्य के क्षेत्र पर आजादी के बाद से ही चली आ रही लालफीताशाही और अनदेखी को गंभीरता से लिया तथा नागरिकों को सहनीय इलाज सुलभ कराने के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य योजनाओं पर काम किया। सरकार ने महंगे इलाज से लोगों को राहत देने के लिए आयुष्मान योजना की शुरुआत की। रिपोर्ट में कहा गया है कि आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं के विस्तार का सीधा असर लोगों के निजी स्वास्थ्य खर्च पर पड़ा है।

मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देशभर में लगभग 2 लाख आयुष्मान आरोग्य मंदिर वैलनेस सेंटर के संचालन ने प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच बढ़ाई है, जिससे लोगों को शुरुआती इलाज और जांच के लिए बहुत कम निजी खर्च करने पड़ रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र और राज्य सरकारों के स्वास्थ्य क्षेत्र में बढ़ते निवेश के कारण सार्वजनिक स्वास्थ्य खर्च में लगातार वृद्धि दर्ज की गई है। इसके साथ ही अस्पताल में भर्ती और गंभीर बीमारियों के इलाज पर गरीब और निम्न आय वर्ग के परिवारों का आर्थिक बोझ कम होता जा रहा है। हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों में गुणवत्ता की चुनौतियां अभी हैं लेकिन सुरक्षा कवरेज बढ़ाने और इलाज के आर्थिक बोझ में कमी का फायदा आम नागरिकों को मिलने लगा है।

भारत के आजाद होने के बाद नागरिकों के समक्ष अनेक समस्याएं थी जिसका समाधान समय के साथ सरकारों ने खोजने का प्रयास किया लेकिन स्वास्थ्य क्षेत्र हमेशा उनकी नजरों से ओझल रहा। हम सभी जानते हैं कि परिवार में कोई भी सदस्य अगर बीमार पड़ जाता तो उस परिवार का पूरा का पूरा आर्थिक ढांचा तबाह हो जाता है। किसी परिवार में हृदय संबंधी या कैंसर संबंधी बीमारी हो जाए तो वह परिवार बिल्कुल बिखर जाता है। केंद्र की वर्तमान सरकार ने आम नागरिकों की समस्या को कल्याणकारी राज्य के नाते गंभीरता से लिया तथा इसके लिए आयुष्मान भारत योजना के तहत बजट आवंटित कर चरणबद्ध तरीके से काम किया। इस योजना का देश में करोड़ों लोगों को लाभ प्राप्त हुआ है।

मालूम हो कि कल्याणकारी राज्य की शुरुआत नेशन स्टेट की अवधारणा से हुई जिसकी नींव 19वीं शताब्दी में पड़ी थी। इससे पहले ब्रिटेन में 1215 में मैग्नाकार्टा, 1688 में ग्लोरियस क्रांति और 1789 में फ्रांस की क्रांति में सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक बदलाव देखने को मिलते हैं। इन बदलाव के साथ–साथ जन मानस ने कल्याणकारी योजनाओं को लेकर भी संघर्ष किया, जिसका परिणाम हुआ कि 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी के आरंभ में राज्यों ने कल्याणकारी योजनाओं को अपनी नीति में सम्मिलित किया। 19वीं शताब्दी से लेकर आज तक राष्ट्र के निर्माण में कल्याणकारी योजनाओं का अहम योगदान रहा है। जर्मनी में बिस्मार्क ने सामाजिक बीमा की शुरुआत की। इसी तरह अमेरिका में कल्याणकारी योजनाएं देखें तो पाते हैं कि सरकार गरीबों के लिए, निचले तबके के लोगों के लिए कई तरह की योजनाएं चल रही हैं जिनमें प्रमुख है मेडिकल, पोषण, सुरक्षा, आवास एवं परिवहन सहायता। यूनाइटेड किंगडम को उदारवादी कल्याणकारी राज्य कहा जाता है जहां स्वास्थ्य शिक्षा रोजगार की योजनाएं चल रही हैं।

भारत में आजादी मिलने से पहले 1930 में प्रोफेसर पीसी महालोनोविस ने योजनाओं का प्रारूप तैयार किया था और 1934 में एम. विश्वेश्वरैया ने प्लानिंग इकोनामी फॉर इंडिया का प्रारूप तैयार किया। इस प्रारूप में सभी मुख्य बिंदुओं पर ध्यान रखा गया ताकि भारत के कल्याणकारी राज्य के साथ–साथ राष्ट्र निर्माण की दिशा में यह योगदान कर सके। राष्ट्र निर्माण तभी संभव है जब कल्याणकारी योजनाओं को सही से क्रियान्वित कर अंतिम कतार में खड़े अंतिम व्यक्ति की भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। 1947 में जब देश आजाद हुआ तब संविधान सभा में सभी बिंदुओं पर बात करके संविधान में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को अंकित किया गया जो अनुच्छेद 36 से 51 तक में वर्णित है।

पिछले 10–12 सालों में देश की सरकार ने सभी क्षेत्रों में बदलाव किया जिसका फायदा भारत की जनता को मिल रहा है। प्राय देखा जा रहा है कि कल्याणकारी योजनाओं से लोगों के जीवन में सुधार आ रहा है। आयुष्मान योजना के तहत अब तक 12 करोड़ से अधिक भर्ती मामलों में लोगों को मुफ्त इलाज मिला। योजना के तहत कुल 1.8 लाख करोड रुपए से अधिक के उपचार हुए हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के 80वें राउंड के अनुसार सरकारी स्वास्थ्य वित्तीय योजनाओं से कवर आबादी की संख्या भी बढ़ी है। शहरी क्षेत्र में 8.5 प्रतिशत से बढ़कर 31.8 प्रतिशत हो गई है। सरकार का कहना है कि योजना का विस्तार जारी है। 70 वर्ष और इससे अधिक उम्र के

पिछले 10–12 सालों में देश की सरकार ने सभी क्षेत्रों में बदलाव किया जिसका फायदा भारत की जनता को मिल रहा है। प्राय देखा जा रहा है कि कल्याणकारी योजनाओं से लोगों के जीवन में सुधार आ रहा है।

नागरिकों को 'आयुष्मान भारत वय वंदन योजना' के तहत कैशलेस इलाज मिल रहा है। अब तक 1.22 करोड़ से अधिक लोग पंजीकरण करा चुके हैं जिनमें से 14.5 लाख से अधिक लोगों का उपचार किया जा चुका है।

इसके अलावा लगभग 37 लाख आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी योजना के दायरे में शामिल किया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि इससे जमीनी स्तर पर काम करने वाली महिला स्वास्थ्य कर्मियों को सामाजिक सुरक्षा मिली है। अपनी रिपोर्ट में सरकार ने योजना की पोर्टेबिलिटी व्यवस्था को भी उपलब्धि बताया है। इसके तहत लाभार्थी देश के किसी भी सूचीबद्ध अस्पताल में अपना इलाज कर सकते हैं।

आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना है जिसके अंतर्गत 5 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा 'मेडिक्लेम' की तरह दिया जाता है, जो गरीब और मध्यम परिवार के लोगों के लिए बनाया गया है। योजना का लक्ष्य 50 करोड़ लोगों को लाभान्वित करने का है।

इसके अतिरिक्त भी केंद्र की सरकार देश के आम नागरिकों को आर्थिक और सामाजिक रूप से समृद्ध करने के लिए अनेक योजनाएं चला रही है। प्रमुख कल्याणकारी योजनाओं की बात करें तो धुएं से छुटकारा दिलाने के लिए उज्ज्वला योजना के तहत हर परिवार को गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया है।

प्रधानमंत्री बीमा योजना के अंतर्गत दो योजनाएं हैं – सुरक्षा योजना एवं जीवन ज्योति योजना। पहली योजना में 2 महीने के प्रीमियम पर 2 लाख का कवर है, और दूसरी योजना में 330 रूपये सालाना भुगतान पर 2 लाख रुपये का बीमा कवर है, जो 18 से 50 वर्ष तक के लोगों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से बनाई गई है। प्रधानमंत्री जन धन योजना ने करोड़ों गरीबों के लिए

आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना है जिसके अंतर्गत 5 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा मेडिक्लेम की तरह दिया जाता है, जो गरीब और मध्यम परिवार के लोगों के लिए बनाया गया है। योजना का लक्ष्य 50 करोड़ लोगों को लाभान्वित करने का है।

बैंकों के दरवाजे खोल दिए। 28 सितम्बर, 2014 को यह योजना लागू हुई, पहले ही दिन डेढ़ करोड़ लोगों ने खाते खोले, जिसमें बिना शुल्क फंड ट्रांसफर, मोबाइल बैंकिंग आदि सुविधाएं शामिल हैं। खाता जीरो बैलेंस से भी खोला जा सकता है।

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना देश की सबसे बड़ी विश्व चर्चित कल्याण योजना है, जिसके अंतर्गत हर गरीब को 5 किलो राशन मुफ्त दिया जाता है, लगभग 80 करोड लोग इस योजना से लाभान्वित हो रहे हैं। इतनी बड़ी खाद्य सुरक्षा योजना विश्व के किसी भी देश में नहीं है। प्रधानमंत्री आवास योजना का लक्ष्य सबके लिए अपना घर है, जिसमें प्रति परिवार 2 लाख 60 हजार रुपये की सब्सिडी का प्रावधान है। केंद्र सरकार की सभी जनकल्याण योजनाओं में खाताधारकों को सीधे रकम भेजी जाती है। कुछ बड़ी योजनाओं जैसे किसान सम्मान निधि, गरीब कल्याण योजना आदि को छोड़कर बाकी योजनाओं के व्यापक प्रचार–प्रसार की आवश्यकता है। हालांकि दूरदराज इलाकों में योजनाओं के बारे में आवश्यक जानकारी के अभाव में लोग ज्यादा लाभान्वित नहीं हो पाते। कुछ राज्यों, जहां केंद्र और राज्य सरकारें अलग–अलग पार्टियों की हैं, में केंद्रीय योजनाओं को गंभीरता से नहीं लिया जाता जिसका नुकसान आम लोगों को होता है। जनकल्याण योजनाओं पर कुछ विपक्षी पार्टियां राजनीति भी करती हैं, जो कि जन हित में नहीं है, इस तरह की सतही राजनीति बंद होनी चाहिए।

बहरहाल सरकार की कल्याणकारी योजना आयुष्मान भारत लोगों के लिए राहत का सबक बनी है। इलाज पर होने वाले खर्च में निजी खर्च की भागीदारी धीरे–धीरे घट रही है। केंद्र की सरकार 'सबका साथ, सबका विकास, सबमें विश्वास और सबका स्वास्थ्य' के नारे को धरातल पर उतरने में धीरे–धीरे कामयाबी हासिल कर रही है। ❑❑

परीक्षाओं पर दिलाना होगा छात्रों का भरोसा

शिक्षा से जुड़े मुद्दे भावनात्मक और राजनीतिक असर डालते हैं। पहले से ही नौकरी की कमी बढ़ती प्रतियोगिता और करियर की अनिश्चिता ने युवाओं में असुरक्षा बढ़ाई है। नीट यूजी की परीक्षा रद्द होने के बाद देश की परीक्षा प्रणाली कटघरे में है। हालांकि सरकार डैमेज कंट्रोल के लिए तमाम एहतियाती कदम उठा रही है। सरकार ने जल्दी से जल्दी परीक्षा की नई तारीख घोषित करने, आवेदन शुल्क लौटने और परीक्षा में बैठने वाले छात्रों को पसंदीदा शहर में केंद्र चुनने का विकल्प दिया है। ऐसे कदमों से सरकार यह बताना चाहती है कि वह छात्रों की परेशानी समझता है और समाधान के लिए भी गंभीर प्रयास कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि छात्रों का भरोसा कैसे लौटे?

मालूम हो कि पिछले 7 वर्षों में यानी वर्ष 2019 से लेकर 15 मई 2026 तक भारत में विभिन्न स्तरीय प्रतियोगी लगभग 70 परीक्षाओं के पेपर लीक हुए। आज तक किसी मामले की जांच पूरी नहीं हुई और ना ही किसी मामले में न्याय हुआ। प्रत्येक मामलों में छोटे स्तर के कर्मचारी पकड़े गए जिन्हें कुछ महीनो बाद जमानत मिल गई। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्यों नहीं दाखिला परीक्षा करने वाली एनटीए को उनकी जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया जाए? एनडीए पर यह भी आरोप है कि वह पुराने तौर तरीकों को अभी भी अपनाती है, वह अपने पुराने सिस्टम में कोई सुधार नहीं करती। इंटरनेट कंप्यूटर और एआई के जमाने में भी प्रश्न पत्र मुद्रित करके परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने में विश्वास करती है। अगर हर हाल में ऐसा ही करना है तो क्यों नहीं प्रश्न पत्रों के अलग–अलग सेट तैयार करके अलग–अलग केंद्रों को भेजा जाए, ताकि कभी इस तरह का हादसा होने पर पूरी परीक्षा रद्द न करनी पड़े। कोई अनहोनी होने पर केवल चिन्हित केदो पर ही दोबारा परीक्षा कराई जाए।

सरकार को पेपर लीक तकनीकी गड़बड़ी मूल्यांकन विभाग और प्रशासनिक लापरवाही पर ठोस कार्रवाई के साथ आगे आने होगा। शिक्षा व्यवस्था में लगे घुन को खत्म करने के लिए पारदर्शिता बढ़ानी होगी जवाबदेही तय करनी होगी। सरकार को आगे जाकर हस्तक्षेप करना ही होगा क्योंकि लंबी चुप्पी से बात नहीं बनेगी।

– शिवनंदन लाल

एनटीए का गठन 2017 में हुआ था। तब से लेकर आज तक इस संस्था की विश्वसनीयता सवालों के घेरे में रही। 5 में 2024 को भी जब इसी नीट परीक्षा में गड़बड़ झाला हुआ तो मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। तब संस्था ने भविष्य में इस तरह की गलती दोबारा न करने का आश्वासन न सिर्फ अदालत को बल्कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय को भी भरोसा दिया था। आलम यह है कि 2 साल बीतते बीतते उससे भी बड़ा कांड उजागर हो गया। पिछली दफा एजेंसी ने कई छात्रों को पूरे पूरे 720 नंबर दे डाले थे जबकि वे छात्र पढ़ने में सामान्य से भी कमजोर थे। इस बार तो देश के विभिन्न शहरों में प्रश्न घूमते रहे। वाजिद खरीदार खोजते रहे।

इंडियन ने अपने पहले सफाई में कहा है कि प्रश्न पत्र प्रिंटिंग प्रेस से लीक हुए जबकि सभी जानते हैं जहां पेपरो की छपाई होती है वहां परिंदा भी पर नहीं मार सकते। वह बेहद गुप्त स्थान होता है और वहां कर्मचारियों को फोन रखने तक की इजाजत नहीं होती। तो जाहिर सी बात है कि इस तरह के कांड में पूरा का पूरा सिंडिकेट शामिल होता है और समय आ गया है कि सरकार इस तरह के गिरोह का पर्दाफाश करें तथा उन्हें कड़ी सजा दे ताकि भविष्य में छात्रों के साथ फिर ऐसा कोई खिलवाड़ ना हो।

इंटरनेट कंप्यूटर और एआई के जमाने में भी प्रश्न पत्र मुद्रित करके परीक्षा केद्रों तक पहुंचने में विश्वास करती है। अगर हर हाल में ऐसा ही करना है तो क्यों नहीं प्रश्न पत्रों के अलग-अलग सेट तैयार करके अलग-अलग केद्रों को भेजा जाए, ताकि कभी इस तरह का हादसा होने पर पूरी परीक्षा रद्द न करनी पड़े। कोई अनहोनी होने पर केवल चिन्हित केदो पर ही दोबारा परीक्षा कराई जाए।

इस पूरे प्रकरण में विपक्ष को बैठे बिठाये एक मुद्दा हाथ लग गया है। इसके बहाने विपक्ष सरकार को लगातार घर रहा है तथा सरकार की पूरा शिक्षा पद्धति पर सवालिया निशान खड़ा कर रहा है। इस बार 12वीं की कॉपियों की जांच में अपनाई गई ऑन स्क्रीन मार्किंग पद्धत भी सवालों के घेरे में है। इसके अलावा एनसीईआरटी की किताबों से जुड़े विवाद, विश्वविद्यालय में जातिगत भेदभाव को रोकने वाले नए नियमों पर रोक और शिक्षा नीति से जुड़े कुछ अन्य फैसले भी सरकार के लिए सम नहीं रहे। विपक्ष और एक वर्ग विशेष के शिक्षाविद लगातार निशाना चाहते रहे हैं।

ऐसे में सिर्फ परीक्षा की नई तारीख घोषित करने और फीस लौटाने से विश्वास की बहाली पूरी तरह से संभव नहीं है। सरकार को पेपर लीक तकनीकी गड़बड़ी मूल्यांकन विभाग और प्रशासनिक लापरवाही पर ठोस कार्रवाई के साथ आगे आने होगा। शिक्षा व्यवस्था में लगे घुन को खत्म करने के लिए पारदर्शिता बढ़ानी होगी जवाबदेही तय करनी होगी। सरकार को आगे जाकर हस्तक्षेप करना ही होगा क्योंकि लंबी चुप्पी से बात नहीं बनेगी। छात्र और उनके अभिभावक सिर्फ सरकार से उम्मीद रखते हैं, उनकी उम्मीदें ना टूटे इसका ख्याल सरकार को रखना ही होगा क्योंकि एक बार भरोसा अगर टूट जाए तो उसे वापस लाना किसी के लिए भी कठिन काम होता है। ❑❑

:: सूचना ::

स्वदेशी पत्रिका आर्थिक सम्राज्यवाद के खिलाफ एक सशक्त आवाज है। पत्रिका को ऐसे लोगों से प्रतिक्रियाएं, रिपोर्ट या आलेख की अपेक्षा है जो राष्ट्रहित में सोचते हैं और देश के स्वावलम्बन के लिए कुछ करने की इच्छा रखते है। जरूरी नहीं कि आप पत्रकार या लेखक ही हों, अपने आसपास से जुड़ी चीजों के प्रति आपकी संवदेना है और आप शब्दों में उसे लिख सकते है तो हमें अवश्य लिख भेजें। साथ ही स्वदेशी पत्रिका में छपे लेख आपको कैसे लगते हैं, क्या आप इसमें कुछ नए विषयों का समायोजन चाहते हैं कृपया हमें अवश्य अवगत कराएं। आपके विचारों को हम प्राथमिकता के साथ प्रकाशित करने का भी प्रयास करेंगे।

संपादक, स्वदेशी पत्रिका

'धर्मक्षेत्र', सेक्टर–8, बाबू गेनू मार्ग, रामकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली–110022

श्रमेव जयते! का यशोगान

हां! मैं हूं मजदूर, मजदूर ही रहूंगा और मजदूर ही मरूंगा। यह करुणा आज भी झंझोर कर शर्मसार करती है। ग्लानि इस मर्ज का मर्म आखिर क्यों नहीं ढूंढ पाए। समझ से परे है। साधन, संसाधन और संपन्नता में कोई कमी नहीं है। फिर मजदूरों का ये हाल कैसा? क्यों हमारा श्रम रोटी– कपडा– मकान और कमाई– पढाई– दवाई की झंझावात में उलझता है? क्या मजदूर जैसा पैदा होता है वैसा ही मर जाए? हरगिज़ भी नहीं! मजदूरों को उनका वाजिब हक और अधिकार मिलना चाहिए, जिसके वह सच्चे हकदार हैं। अभिलाषा, समृद्ध श्रम नीति सुदृढ़ राष्ट्र क्रांति का अनुष्ठान करेगी। कर्मवीरता में राष्ट्र का विकास और जन–जन का कल्याण निहित है। आईए, हम सब मिलकर मैं मजदूर हूं, मैं मजबूत हूं के श्रमोमय से राष्ट्रोदय की ओर आगे बढ़े।

मजदूर आज मजबूर

अगर हम बात करें तो मानव शक्ति, दिमागी कार्य, शारीरिक बल और प्रयास करने वाली है। जो काम को मेहनत के द्वारा अपनी श्रम शक्ति को बेचें, उसी का नाम मजदूर है। मजदूर ही देश के विकास की रीढ की हड्डी। मजदूर के पसीने से मुल्क लहलहाता है। सही मायनों में कहे तो मजदूर ही भाग्य विधाता है। अलबत्ता भाग्य विधाता ही अपने भाग्य को खोज रहा है? मजदूर आज मजबूर बनकर कर्मपथ पर चलकर श्रम से लथपथ हो रहा है। इसके कारण और कारक किसे माने, सरकारें, नियत, नीति, नेतृत्व, लालफीताशाही या अफसरशाही को, जो खोजे नहीं मिल रहा है। मिल जाता तो हमारे श्रमवीरों की हालतें ऐसी नहीं होती। बावजूद खोज खबर लेने की फ्रिक किसी को नहीं है?

एक मई अर्थात मई दिवस, जिसे श्रमिक दिवस या अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस भी कहा जाता है। यह वह दिन है जब श्रमिकों और श्रमिक आंदोलन द्वारा किए गए संघर्षों और उपलब्धियों को याद किया जाता है।

– हेमेन्द्र क्षीरसागर

कल्याण का अनुष्ठान

एक मई अर्थात मई दिवस, जिसे श्रमिक दिवस या अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस भी कहा जाता है, यह वह दिन है जब श्रमिकों और श्रमिक आंदोलन द्वारा किए गए संघर्षों और उपलब्धियों को याद करता है। इंकलाब जिंदाबाद! हम अपना हक मांगते ना किसी से भीख मांगते। आवाज दो! हम एक हैं। दुनिया के मजदूरों, एक हो जाओ! जैसे सशक्त नारे। और मेहनतकशों, एकजुट हो जाओ! सारी सड़कों पर गूँज उठा। मजदूर दिवस दुनिया भर में श्रमिकों के प्रयासों का सम्मान करने और उन्हें शोषण से बचाने के लिए मनाया जाता है। आज ये कहीं न कहीं आयोजनों, भाषणों और कवायदों तक सीमित रह गया है, साफ़–साफ़ दिखाई पड़ता है। न कि मजदूर उत्थान, कल्याण और विकास का अनुष्ठान बनता हुआ दिखता है।

कानूनी संरक्षण

दरअसल, अभिरक्षा में कारखाना अधिनियम, 1948, औद्योगिक संघर्ष अधिनियम, 1947, भारतीय श्रम संघ अधिनियम, 1926, भृति–भुगतान अधिनियम, 1936, श्रमजीवी क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923 इत्यादि उद्योग तथा श्रम सम्बन्धी विधान की श्रेणी में आते हैं। हमारे संविधान में मजदूर को सम्मान जनक काम और मजदूरी देने के साथ–साथ कानूनी संरक्षण दिया है। काम का अधिकार और पूरी मजदूरी देने का प्रावधान कर शोषण से बचाने के लिए अलग सें श्रम विधि का गठन कर शोषण कर्ता को दंड का प्रावधान भी किया गया है। अब कोई भी नियोजित ठेकेदार, कारखाना मालिक मजदूरों का शोषण नहीं कर सकता है। लेकिन अब तक जो उनकी नोटिस बोर्ड तक ही सीमित दिखाई पड़ता है। इसे धरातल पर लाना होगा।

कोई सुध ले–ले

बाकायदा, अर्धकुशल–अकुशल, कुशल–उच्च कुशल, दैनिक वेतन भोगी–संविदा कर्मी, अस्थाई–स्थाई, आउटसोर्सिंग– ठेकेदारी भांति–भांति के फेर में अल्प वेतन और नियमितीकरण की भेंट चढ़ना हमारे मजदूरों की फितरत बन गई है। वह जैसा था, आज भी वैसा ही है, ये वाजिब नहीं है। वह सामान्य कार्य–सम्मान वेतन। सम्मान सुरक्षा, सुविधाएं और न्याय की मांग करते–करते थक गया। धरना, प्रर्दशन, आंदोलनों और रैलियों में उनकी ऊर्जा नष्ट हो गई। बजाए कोई सुध लेता। एक मजदूर, मजबूत भारतीय होकर भी मजबूर हो गया। इन्हें जियो और जीने दो का अधिकार तो मिलना चाहिए, क्योंकि श्रमशक्ति ही राष्ट्र की शक्ति है। तभी श्रमोमय से राष्ट्रोदय की कल्पना साकार होगी। यथेष्ट, श्रमेव जयते! का यशोगान जन– गण में होगा। अन्यथा श्रम तार–तार होता रहेगा! ❑❑

(हेमेन्द्र क्षीरसागर, पत्रकार, लेखक व स्तंभकार)

:: सदस्यता संबंधी सूचना ::

अधिक जानकारी के लिए देखें :
http://swadeshionline.in/

मान्यवर,

स्वदेशी पत्रिका आज देश में चल रहे स्वदेशी आंदोलनों का स्थापित प्रतीक बन चुकी है। पिछले कई वर्षों से स्वदेशी पत्रिका ने असंगत एवं एकतरफा वैश्वीकरण, जनविरोधी आर्थिक उदारीकरण के विरोध एवं वैकल्पिक और रचनात्मक स्वदेशी आंदोलन के पक्ष में एक सक्रिय प्रहरी के नाते हमेशा आपको जागरूक बनाया है एवं आपसे संवाद स्थापित किया है। विगत कालखंड में इन सभी मुद्दों पर हमें आप जैसे सजग पाठकों का अपेक्षित सहयोग भी मिलता रहा है और भविष्य में भी मिलेगा ऐसा, विश्वास है।

आपसे आग्रह है कि स्वदेशी पत्रिका की आपकी सदस्यता अवधि यदि समाप्त हो गई हो तो कृपया पिछले समय से आगामी वर्ष तक की राशि धनादेश (मनीआर्डर), चेक एवं मांग पत्र (डिमांड ड्राफ्ट) के माध्यम से शीघ्र भेजने की कृपा करें। पत्रिका के लिफाफे के उपर चिपकाए गए पते की प्रथम पंक्ति में सदस्यता अवधि अंकित है। आप अपनी सदस्यता राशि ''स्वदेशी पत्रिका'' के नाम पत्रिका के कार्यालय के पते पर भेज सकते हैं। सदस्यता अद्यतन न हो पाने की स्थिति में वित्तीय कारणों से पत्रिका आगे जारी रखना कठिन होगा।

सदस्यता शुल्क निम्न प्रकार है :–

स्वदेशी पत्रिका	*वार्षिक*	*आजीवन*
हिन्दी	150 रुपए	1500/– रुपए
अंग्रेजी	150 रुपए	1500/– रुपए

हमें आपका सहयोग स्वदेशी आंदोलन को राष्ट्रव्यापी एवं जनोन्मुखी बनाने में प्रमुख भूमिका निभाएगा। कृपया स्वदेशी पत्रिका स्वयं भी पढ़ें एवं अन्य को भी पढ़ने के लिए प्रेरित करें। पत्रिका के संबंध में अपना निष्पक्ष विचार हमें अवश्य भेजें।

आप सीधे बैंक ऑफ इंडिया, खाता नं. **602510110002740, IFSC : BKID- 0006025 (Ramakrishnapuram)** में जमा करवा सकते हैं और उसकी रसीद और अपना पता आप कार्यालय में अवश्य भेजे।

स्वदेशी पत्रिका कार्यालय, 'धर्मक्षेत्र' शिव शक्ति मंदिर, सैक्टर–8, रामकृष्णपुरम्, नई दिल्ली–22

आईआईटी रुड़की में

"विजन 2047 – समृद्ध एवं महान भारत 2.0" पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन

आईआईटी रुड़की ने स्वदेशी शोध संस्थान के सहयोग से अपने दीक्षांत समारोह हॉल में "विजन 2047: समृद्ध एवं महान भारत 2.0" पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया, जिसमें प्रख्यात शिक्षाविदों, नीति–निर्माताओं और उद्योग जगत के नेताओं ने भारत के विकासात्मक रोडमैप पर विचार–विमर्श किया।

उद्घाटन सत्र की शुरुआत मंच पर उपस्थित विशिष्ट गणमान्य व्यक्तियों के औपचारिक स्वागत के साथ हुई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में हिमाचल प्रदेश के माननीय राज्यपाल श्री काविंदर गुप्ता जी की गरिमामयी उपस्थिति रही। मंच पर उपस्थित अन्य विशिष्ट अतिथियों में प्रो. के.के. पंत, निदेशक, आईआईटी रुड़की; प्रो. यू.पी. सिंह, उप–निदेशक, आईआईटी रुड़की; प्रो. एन.पी. पाध्य, निदेशक, एमएनआईटी जयपुर; प्रो. सोमनाथ सचदेवा, कार्यकारी अध्यक्ष, स्वदेशी शोध संस्थान; प्रो. अजीत चतुर्वेदी, कुलपति, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय; तथा प्रो. सुरेखा डंगवाल, कुलपति, दून विश्वविद्यालय शामिल रहे, जिनकी गरिमामयी उपस्थिति ने कार्यक्रम को विशेष महत्व प्रदान किया।

कार्यक्रम का शुभारंभ राष्ट्रगान, कुलगीत एवं दीप प्रज्ज्वलन के साथ हुआ, जिसके पश्चात अतिथियों का सम्मान किया गया। अपने स्वागत भाषण में प्रो. के.के. पंत ने वर्ष 2047 तक आत्मनिर्भर और समृद्ध भारत के निर्माण में शिक्षा, शासन और उद्योग के बीच सहयोगात्मक प्रयासों के महत्व पर बल दिया। उन्होंने उद्योग के सहयोग से गुणवत्तापूर्ण उत्पाद–आधारित अनुसंधान को बढ़ावा देने और उद्यमिता नवाचार को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। प्रो. सोमनाथ सचदेवा ने विषय–परिचय प्रस्तुत करते हुए राष्ट्रीय विकास, नवाचार और नीतिगत सुधारों पर चर्चा की दिशा निर्धारित की। उद्घाटन सत्र का एक प्रमुख आकर्षण राष्ट्रीय रोजगार नीति का परिचय और शुभारंभ रहा, जो रोजगार सृजन और आर्थिक सुदृढ़ता की दिशा में एक दूरदर्शी पहल को दर्शाता है।

कार्यक्रम में कई प्रभावशाली संबोधन शामिल रहे, जिनमें विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह का वर्चुअल संबोधन तथा स्वदेशी जागरण मंच के श्री सतीश कुमार (अ.भा. सह–संगठक) का मुख्य भाषण शामिल था। भारत एक्सप्रेस न्यूज़ नेटवर्क के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक श्री उपेंद्र राय तथा प्रो. अजीत चतुर्वेदी ने भी राष्ट्र निर्माण और उच्च शिक्षा पर अपने विचार साझा किए। श्री के.एन. रघुनंदन ने राष्ट्रीय विकास में शैक्षणिक संस्थानों की भूमिका पर प्रकाश डाला, इसके पश्चात स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री जे.पी. नड्डा का वर्चुअल संबोधन हुआ।

मुख्य अतिथि श्री काविंदर गुप्ता ने अपने विस्तृत संबोधन में भारत की विकास यात्रा पर प्रकाश डालते हुए वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु समेकित नीतिगत ढांचे की आवश्यकता पर बल दिया।

सम्मेलन में देश–विदेश के 100 से अधिक संस्थानों की भागीदारी रही, जिसमें विजन 2047 के अनुरूप समावेशी आर्थिक विकास, तकनीकी नवाचार, रोजगार सृजन, सतत् विकास तथा वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी एवं आत्मनिर्भर भारत के निर्माण जैसे विषयों पर केंद्रित विचार–विमर्श किया गया।

उद्घाटन समारोह शैक्षणिक गहराई और सांस्कृतिक गरिमा का सशक्त संगम रहा, जिसने नीति–निर्माताओं, शिक्षाविदों और उद्योग जगत के नेताओं के बीच संवाद के लिए एक सशक्त मंच प्रदान किया। राष्ट्रीय रोजगार नीति का शुभारंभ इस सत्र का प्रमुख आकर्षण रहा, जिसने भविष्य उन्मुख कौशल और कार्यबल परिवर्तन पर सार्थक चर्चा को प्रेरित किया। विशिष्ट अतिथियों की उपस्थिति, प्रेरणादायक विचारों और दूरदर्शी पहलों के अनावरण ने सम्मेलन के लिए एक सकारात्मक दिशा निर्धारित की।

गणमान्य अतिथियों ने सेंटर फॉर प्रिसीजन मैन्युफैक्चरिंग का भौतिक उद्घाटन भी किया, जो भारी उद्योग मंत्रालय (एमएचआई), सेवरन, फॉर्विया हेल्ला, आई–हब दिव्यसम्पर्क, आईसीएटी, ओमरॉन तथा अन्य उद्योग भागीदारों के सहयोग से स्थापित एक महत्वपूर्ण पहल है, जो संस्थान के बुनियादी ढांचे के विकास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि को दर्शाता है। इस पहल के अंतर्गत विकसित सुविधाएं प्रो. अक्षय द्विवेदी के मार्गदर्शन एवं नेतृत्व में स्थापित की गई हैं, जिनका इस उन्नत अनुसंधान अवसंरचना के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान रहा है।

दौरे के दौरान गणमान्य अतिथियों ने आईआईटी रुड़की के इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) प्रयोगशाला का भी निरीक्षण किया, जहां उन्होंने उन्नत उपकरणों और चल रहे अनुसंधान कार्यों का अवलोकन किया। प्रतिनिधिमंडल को "दिव्यांगजन हेतु सुलभ गतिशीलता वाहन" भी प्रस्तुत किया गया, जिसे याली मोबिलिटी द्वारा आरती फाउंडेशन, आईआईटी रुड़की, भारी उद्योग मंत्रालय (एमएचआई) और इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी (आईसीएटी) के सहयोग से विकसित किया गया है। यह वाहन समावेशी डिजाइन और तकनीकी नवाचार का उत्कृष्ट उदाहरण है, जो दिव्यांगजनों के लिए गतिशीलता समाधान को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।

सम्मेलन के अंतर्गत एक आकर्षक प्रदर्शनी सत्र भी आयोजित किया गया, जिसमें कई स्टार्टअप्स ने अपनी अत्याधुनिक तकनीकों और नवाचारों का प्रदर्शन किया, जो नवाचार–आधारित विकास और आत्मनिर्भरता के विजन 2047 के लक्ष्य में उद्यमिता की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है।

उद्घाटन समारोह ने सम्मेलन के लिए एक सशक्त आधार तैयार किया, जिसका उद्देश्य एक समृद्ध एवं वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी भारत के निर्माण हेतु नवाचार और क्रियाशील रणनीतियों को बढ़ावा देना है। ❑❑

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2255603&reg=3&lang=2

प्रधानमंत्री की मितव्ययता अपील स्वदेशी का ही आह्वान हैः एसजेएम

स्वदेशी जागरण मंच (एसजेएम) ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मितव्ययता संबंधी प्रयासों से भारत की दूसरे देशों पर निर्भरता कम होगी और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा की बचत होगी।

एसजेएम की यह टिप्पणी ऐसे समय में आयी है जब मोदी ने अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए ईंधन के विवेकपूर्ण उपयोग, सोने की खरीद और विदेश यात्रा को स्थगित करने जैसे उपायों का आह्वान किया।

एसजेएम के राष्ट्रीय सह–संयोजक डॉ. अश्वनी महाजन ने एक बयान में कहा कि इन सभी उपायों का उद्देश्य आयात पर निर्भरता कम करना और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा की बचत करना है। उन्होंने कहा, ''स्वदेशी जागरण मंच का दृढ़ विश्वास है कि प्रधानमंत्री की अपील स्वदेशी (स्थानीय स्तर पर उत्पादित वस्तुओं का उपयोग) का आह्वान मात्र है।''

महाजन ने कहा कि पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने से न केवल विदेशी मुद्रा की बचत होगी, बल्कि आपूर्ति में व्यवधान के कारण होने वाली कमी से प्रभावी ढंग से निपटने में भी देश को मदद मिलेगी।

पश्चिम एशिया संघर्ष का जिक्र करते हुए महाजन ने कहा कि एसजेएम आपूर्ति में व्यवधान और बढ़ती कीमतों के प्रभाव को कम करने के लिए आयातित तेल एवं गैस पर निर्भरता कम करने की अपील करता रहा है।

उन्होंने कहा, ''प्रधानमंत्री की सशक्त अपील का राष्ट्रीय मानसिकता पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। इससे न केवल लोग पेट्रोलियम उत्पादों की खपत कम करने के लिए प्रोत्साहित होंगे, बल्कि वैज्ञानिकों, शिक्षाविदों और उद्योगों को भी रोजमर्रा की जरूरतों में पेट्रोलियम उत्पादों के स्थान पर नए विकल्पों की खोज करने की प्रेरणा मिलेगी।''

उन्होंने इलेक्ट्रिक वाहन, सौर ऊर्जा उपकरणों, पवन ऊर्जा उपकरणों जैसे स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं हरित ऊर्जा में भारत के आत्मनिर्भर बनने पर जोर देते हुए कहा, ''एक बार जब भारत स्वच्छ ऊर्जा और प्रौद्योगिकी विनिर्माण में आत्मनिर्भर हो जाएगा, तो देश न केवल कच्चे तेल के आयात के लिए तेल उत्पादक और निर्यातक देशों पर अपनी निर्भरता कम करेगा, बल्कि सौर एवं पवन ऊर्जा उपकरण, इलेक्ट्रिक वाहन के पुर्जे और अन्य उत्पादों के लिए चीन और अन्य देशों पर अपनी निर्भरता भी कम करेगा।''

मालूम हो कि गत दिनों हैदराबाद (तेलंगाना) में प्रदेश भाजपा द्वारा आयोजित एक रैली को संबोधित करते हुए, मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा संरक्षण के लिए पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने, शहरों में मेट्रो सेवाओं का उपयोग करने, कार पूलिंग करने, इलेक्ट्रिक वाहनों का अधिक उपयोग करने, पार्सल परिवहन के लिए रेलवे सेवाओं का उपयोग करने और घर से काम करने का सुझाव दिया था।

https://hindi.theprint.in/india/pms-appeal-for-frugality-is-a-call-for-swadeshi-sjm/970719/

स्वदेशी केवल विचार नहीं, आत्मनिर्भर भारत का आधार : कश्मीरी लाल

स्वदेशी जागरण मंच की अखिल भारतीय चिंतन बैठक के शुभारंभ की पूर्व संध्या पर होटल अनुरागा पैलेस (सवाई माधोपुर) में "स्वदेशी संवाद" कार्यक्रम का गरिमामय आयोजन किया गया। कार्यक्रम में शिक्षा, व्यापार, उद्योग, कृषि एवं सामाजिक जीवन सहित समाज के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े प्रबुद्ध नागरिकों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता करते हुए स्वदेशी, आत्मनिर्भरता एवं भारतीय जीवनदृष्टि पर सार्थक मंधन किया।

कार्यक्रम के मुख्य वक्ता स्वदेशी जागरण मंच के अखिल भारतीय संगठक श्री कश्मीरी लाल ने अपने उद्‌बोधन में कहा कि स्वदेशी केवल देश में निर्मित वस्तुओं के उपयोग तक सीमित नहीं है. बल्कि यह भारतीय जीवनदृष्टि, आत्मगौरव, स्थानीय अर्थव्यवस्था के संरक्षण एवं प्रकृति के साथ संतुलित विकास का व्यापक विचार है। उन्होंने कहा कि स्वदेशी व्यक्ति को अंधानुकरण एवं उपभोक्तावाद से निकालकर समाज, संस्कृति और राष्ट्रहित को केंद्र में रखकर जीवन जीने की प्रेरणा देता है। उन्होंने नागरिकों से आह्वान किया कि स्वदेशी को केवल विचार के रूप में नहीं, बल्कि दैनिक जीवन की व्यवहारिक शैली के रूप में अपनाया जाए।

राष्ट्रीय संयोजक श्री आर. सुन्दरम ने वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों, आर्थिक अस्थिरता, ऊर्जा संकट एवं बढ़ती उपभोक्तावादी प्रवृत्तियों का उल्लेख करते हुए कहा कि आज पूरा विश्व पुनः स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं, विकेंद्रीकृत

उत्पादन एवं आत्मनिर्भर व्यवस्था की आवश्यकता को अनुभव कर रहा है। उन्होंने कहा कि स्वदेशी की विचारधारा केवल भारत के लिए ही नहीं, बल्कि संपूर्ण विश्व के लिए संतुलित एवं स्थायी विकास का प्रभावी मॉडल प्रस्तुत करती है। स्वदेशी स्थानीय संसाधनों, कौशल एवं श्रम को सम्मान देकर आर्थिक सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त करता है तथा समाज को आत्मविश्वासी एवं आत्मनिर्भर बनाता है।

इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त करते हुए अखिल भारतीय महिला प्रमुख अर्चना मीना ने कहा कि स्वदेशी भारत की आत्मा, आत्मसम्मान और आत्मनिर्भर भविष्य का आधार है। स्थानीय उत्पादों, कौशल एवं संसाधनों को अपनाकर ही मजबूत राष्ट्र निर्माण की दिशा में सार्थक योगदान दिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि स्वदेशी का भाव समाज में आर्थिक सम्यक्तिकरण के साथ–साथ सांस्कृतिक चेतना एवं राष्ट्रीय स्वाभिमान को भी मजबूत करता है।

कार्यक्रम के दौरान उपस्थित नागरिकों के बीच स्वदेशी के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं पर्याहरणीय आयामों पर विस्तृत एवं सार्थक संवाद हुआ। पूरे वातावरण में राष्ट्रचिंतन, भारतीयता एवं आत्मनिर्भर भारत के संकल्प की स्पष्ट अनुभूति दिखाई दी।

अंत में अर्चना मीना ने सभी अतिथियों, वक्ताओं एवं सहभागियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसे संवाद समाज में जागरूकत्ता एवं सकारात्मक परिवर्तन के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। कार्यक्रम का समापन स्वदेशी विचार को जन–जन तक पहुँचाने तथा उसे व्यवहार में उतारने के संकल्प के साथ हुआ।

https://vikalptimes.com/swadeshi-samvad-programme-held-at-hotel-anuraga-palace-ranthambore-sawai-madhopur/

प्रधानमंत्री की अपील का समर्थन सोना नहीं देश चुनें: स्वजामं

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ईंधन की कम खपत व सोना खरीद रोकने की अपील को राजधानी भोपाल में समर्थन मिला है। स्वदेशी जागरण मंच द्वारा सोमवार को जन जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें लोगों से विदेशी चीजों का त्यागकर स्वदेशी अपनाने की अपील की गई। इस दौरान मंच के लोग हाथों में तख्तियां लिए नजर आए, जिसमें लिखा था, ''सोना नहीं, देश चुनें''। विदेशी सोने का मोह छोड़कर भारत को आत्मनिर्भर बनाने में अपना योगदान दें।

तेलंगाना के सिकंदराबाद में आयोजित एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एक साल सोना न खरीदने की लोगों से अपील की। वैश्विक संकट को देखते हुए पीएम मोदी ने इसके साथ तेल व ईंधन की खपत कम करे, पब्लिक

ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने और वर्क फ्रॉम होम करने की अपील की है। इसके बाद भोपाल के एमपी नगर में सोमवार को स्वदेशी जागरण मंच ने स्वदेशी चीजों का उपयोग करने और विदेशी वस्तुओं को त्यागने की लोगों से अपील की है। मंच ने अपील करते हुए कहा कि यातायात के लिए स्वयं के वाहन चलाने के बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर निर्भर रहें, जिससे ईंधन बचेगा और देश का पैसा देश में ही रहेगा।

मंच की महिला कार्य प्रमुख सीमा भारद्वाज ने बताया, "हम जन जागरूकता के लिए पिछले लगातार अभियान चला रहे हैं, जिसमें लोगों को ईंधन बचाने का संदेश दिया जा रहा है और साथ ही स्वदेशी सामानों को अपनाने की अपील की जा रही है। अगर हम जागरूक होकर इन पहल का पालन करेंगे तो देश आर्थिक रूप से मजबूत होगा और देश का पैसा भी बाहर नही जाएगा। छोटे–छोटे कामों के लिए लोगों से पैदल चलकर अपने कामों को पूरा करने का आवाहन किया।"

मंच की महिला कार्य प्रमुख सीमा भारद्वाज ने बताया, "अगर हम जागरूक होकर इन पहल का पालन करेंगे तो देश आर्थिक रूप से मजबूत होगा और देश का पैसा भी बाहर नहीं जाएगा। हमने छोटे–छोटे कामों के लिए लोगों से पैदल चलकर अपने कामों को पूरा करने की अपील की।"

https://www.etvbharat.com/hi/state/bhopal-swadeshi-jagran-manch-launched-public-awareness-campaign-appeal-to-adopt-swadeshi-mps26051106375

स्वजामं ने शुरु किया पक्षी संरक्षण और ऊर्जा बचत अभियान

चिलचिलाती धूप और आसमान से बरसती आग के बीच बेजुबान पक्षियों के संरक्षण और राष्ट्र की ऊर्जा संपदा को बचाने के लिए स्वदेशी जागरण मंच ने एक सशक्त मानवीय एवं राष्ट्रीय पहल की है। दिनांक 12 मई 2026 को राजस्थान के गंगापुर सिटी स्थित पुरानी अनाज मंडी के पार्क में स्वदेशी जागरण मंच द्वारा आयोजित विशेष कार्यक्रम में जहाँ एक ओर पेड़ों पर परिंडे बांधकर पक्षियों की प्यास बुझाने का संकल्प लिया गया, वहीं दूसरी ओर नागरिकों को

ऊर्जा एवं ईंधन बचाने के प्रति जागरूक करने हेतु एक व्यापक अभियान का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम का आगाज करते हुए मंच के कार्यकर्ताओं ने सार्वजनिक स्थानों और वृक्षों पर मिट्टी के परिंडे बांधे और उनमें शीतल जल भरा। नगर संयोजक गोपाल बैराडा एवं नगर प्रचार प्रमुख रोहित गुप्ता ने मंच की सामाजिक प्रतिबद्धता को दोहराते हुए कहा कि पूरे भारतवर्ष में सक्रिय स्वदेशी जागरण मंच इस भीषण गर्मी में पक्षियों के अस्तित्व को बचाने हेतु निरंतर कार्य कर रहा है। इस दौरान उपस्थित सभी सदस्यों ने इन परिंडों में नियमित रूप से पानी भरने का सामूहिक संकल्प लिया। कार्यक्रम में उत्साहवर्धन हेतु संयोजक मोहनलाल शर्मा एवं पूरणमल गुप्ता ने उपस्थित अतिथियों एवं सदस्यों का तिलक लगाकर और दुपट्टा पहनाकर आत्मीय स्वागत व अभिनंदन किया।

आयोजन के दौरान मुख्य वक्ता महेश गुप्ता सर्वेयर ने ऊर्जा एवं ईंधन संरक्षण के विशेष जागरूकता अभियान की महत्ता पर प्रकाश डाला। उन्होंने रेखांकित किया कि घरों, कार्यालयों और सार्वजनिक स्थलों पर अनावश्यक रूप से चलते पंखे, कूलर, एसी और लाइटें ऊर्जा की भारी बर्बादी का कारण बनती हैं। उन्होंने आह्वान किया कि नागरिक अपनी दैनिक आदतों में सुधार करें और राष्ट्र की ऊर्जा संपदा को सुरक्षित करने के लिए उपयोग में न आने वाले उपकरणों को बंद करने की आदत डालें। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक नागरिक को राष्ट्र के प्रति उनकी जिम्मेदारी का बोध कराना है। इस महत्वपूर्ण अवसर पर नगर संपर्क प्रमुख अरविंद गोयल, नगर वित्त संयोजक अनिल कुमार जैन, नगर सेवा प्रमुख ओमप्रकाश जी पीएनबी, नगर पर्यावरण प्रमुख केशव गुप्ता, विवेक खंडेलवाल, अमित कुमार खंडेलवाल, भगवान सहाय कंपाउंडर, अंशुल कुमार गुप्ता, दीपक सोनी, रामचंद्र मखीजा, हरिचरण गुप्ता, मनीष गुप्ता, विष्णु कुमार अग्रवाल, कल्याण प्रसाद, संतोष मसाबता, सुनील कुमार गर्ग और संतोष नारोली सहित संगठन के अनेक गणमान्य सदस्य उपस्थित रहे। यह आयोजन न केवल जीव–दया का प्रतीक बना, बल्कि राष्ट्र निर्माण हेतु ऊर्जा संरक्षण की दिशा में भी एक मील का पत्थर साबित हुआ।

https://www.pratahkal.com/sawai-madhopur/bjp-district-training-camp-bauli-sawai-madhopur-1591956

स्वदेशी जागरण मंच का जिला विचार वर्ग सम्पन्न

स्वदेशी जागरण मंच के तत्वावधान में जिला विचार वर्ग का आयोजन वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय में सम्पन्न हुआ। कार्यक्रम में स्वदेशी विचार, आत्मनिर्भर भारत, भारतीय अर्थनीति तथा वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में स्वदेशी की प्रासंगिकता जैसे विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता प्रांत समन्वयक डॉ. अखिलेश त्रिपाठी ने कहा कि वर्तमान समय में आर्थिक आत्मनिर्भरता ही राष्ट्र की वास्तविक शक्ति है। उन्होंने कहा कि विदेशी उपभोग आधारित व्यवस्था भारतीय संस्कृति, रोजगार और स्थानीय उद्योगों के लिए चुनौती बनती जा रही है। स्वदेशी अपनाकर ही भारत वैश्विक स्तर पर सशक्त नेतृत्व कर सकता है। प्रांत मेला प्रमुख डॉ. अरुण त्रिपाठी ने अपने उद्‌बोधन में कहा कि स्वदेशी केवल आर्थिक विचार नहीं, बल्कि यह भारतीय जीवन पद्धति का मूल तत्व है। उन्होंने युवाओं से स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का आह्वान किया। प्रांत कार्यकारिणी सदस्य प्रो. सुरेश कुमार पाठक ने कहा कि वैश्वीकरण के इस दौर में भारतीय शिक्षा, संस्कृति और रोजगार व्यवस्था को सुरक्षित रखने के लिए स्वदेशी चिंतन अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने बताया कि स्वदेशी भाव से ही सामाजिक समरसता और आर्थिक संतुलन स्थापित किया जा सकता है। प्रांत कार्यकारिणी सदस्य डॉ. विवेक कुमार मिश्र ने तकनीकी और डिजिटल क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता पर जोर देते हुए कहा कि भारतीय युवाओं को नवाचार एवं उद्यमिता के माध्यम से स्वदेशी को नई दिशा देनी होगी। जिला संरक्षक प्रो. अजय द्विवेदी ने कहा कि स्वदेशी विचार समाज को आत्मविश्वास प्रदान करता है तथा स्थानीय संसाधनों के समुचित उपयोग से देश आर्थिक रूप से मजबूत बन सकता है। जिला संयोजक डॉ. प्रशांत त्रिवेदी ने कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए कहा कि स्वदेशी जागरण मंच समाज के विभिन्न वर्गों तक स्वदेशी विचार पहुंचाने का सतत कार्य कर रहा है। जिला समन्वयक डॉ. मनोज पांडेय ने सभी अतिथियों एवं प्रतिभागियों के प्रति आभार व्यक्त किया तथा कहा कि स्वदेशी के माध्यम से ही भारत विश्वगुरु बनने की दिशा में आगे बढ़ सकता है। कार्यक्रम में उद्देश्य सिंह, आदित्य कुमार, डॉ. जे. पी. सिंह, ममता सिंह, शिवानी ओझा सहित अनेक कार्यकर्ता एवं गणमान्य लोग उपस्थित रहे।❑❑

स्वदेशी गतिविधियां

स्वदेशी कार्यक्रम

सचित्र झलक

प्रांत सम्मेलन (उड़ीसा-पूर्व)

जिला विचार वर्ग, शाजापुर

पटना, बिहार

विचार वर्ग, रोहिणी (दिल्ली)

स्वदेशी पत्रिका डाक तिथि 15–16 मई 2026
एल.पी.सी. दिल्ली, दिल्ली पी.एस.ओ., दिल्ली आर.एम.एस. दिल्ली–06
प्रकाशन तिथि : प्रत्येक माह 10 तारीख

डाक पंजी. संख्या DL-SW/01/4074/2024-26
रजि. आर.एन.आई. पंजी. संख्या 64697/96

स्वदेशी गतिविधियां

"विजन 2047 - समृद्ध एवं महान भारत 2.0"

पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन, आईआईटी रुड़की

सचित्र झलक

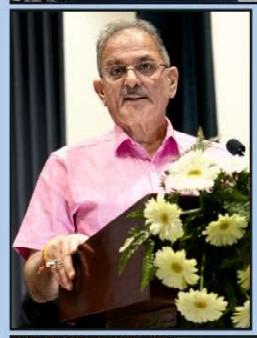

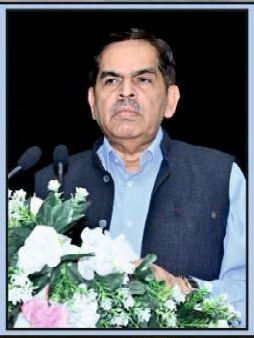

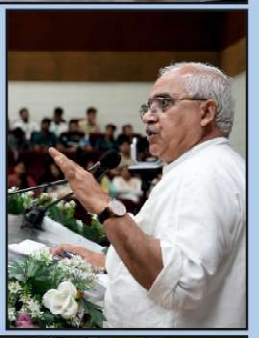

स्वदेशी संवाद

सवाई माधोपुर, राजस्थान

प्रकाशक व मुद्रक डॉ. अश्वनी महाजन द्वारा स्वदेशी जागरण समिति के लिए काम्पीटेंट बाईन्डर्स (प्रिंटिंग यूनिट), नवीन शाहदरा, दिल्ली से मुद्रित और धर्मक्षेत्र, सेक्टर–8, रामाकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली–110022 से प्रकाशित, संपादकः अजेय भारती